Useful For Prelims

Date: 21 January 2026

क्रोमेटिन बायोलाजी अनुसंधान शुरू करने वाले पहले विज्ञानी थे प्रो.राव

प्रोफेसर एमआरएस राव का जन्म 1948 में आज ही मैसूरु में हुआ था। 1973 में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) से जैव रसायन विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1974-76 तक ह्यूस्टन स्थित बेयलर कालेज आफ मेडिसिन में पोस्टडाक्टोरल शोध कार्य किया। भारत लौटने पर उन्होंने आइआइएससी के जैव रसायन विभाग में कार्यभार संभाला। यहां उन्होंने अपनी प्रयोगशाला के माध्यम से कैंसर जीव विज्ञान और क्रोमेटिन संरचना के क्षेत्र में मौलिक शोध कार्य शुरू किया। उन्होंने 125 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और 30 से ज्यादा पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन किया है। 2010 में पद्मश्री से सम्मानित हुए।

नई दिल्ली में नासा की सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने अनुभवों को साझा करती हुई।

Hindustan Page
Dainik Bhaskar
Jansatta Page

Sci & Tech

उतक को फिर से बनाने वाली कोशिकाओं की पहचान

अध्ययन ▸ कैंसर, जलने वाले पीड़ितों के लिए आशा की किरण, कैंसर के दोबारा होने से रोक सकती है यह खोज

यह प्रभाव पहली बार 1970 के दशक में फल मक्खियों में देखा गया था

तेल अवीव, एएनआइ/टीपीएस: विज्ञानियों ने पहली बार उन विशेष कोशिकाओं की पहचान की है जो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ऊतकों को फिर से बनने देते हैं। यह एक खोज है जो कैंसर के दोबारा होने से रोकने के तरीके को बदल सकती है। यह जानकारी वाइजमैन इंस्टीट्यूट आफ साइंस के शोधकर्ताओं ने इजराइल प्रेस सर्विस को दी।

उनका अध्ययन हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यह एक ऐसे घटना पर केंद्रित है, जिसे दशकों से "प्रतिपूरक वृद्धि" के रूप में जाना जाता है। इस क्षमता में ऊतक रेडिएशन के कारण बड़ी संख्या में कोशिकाओं के नष्ट होने के बाद फिर से पैदा होते हैं। यह प्रभाव पहली बार 1970 के दशक में फल मक्खियों में देखा गया था, लेकिन अब तक विज्ञानियों को यह नहीं पता था कि कौन सी कोशिकाएं इसके लिए जिम्मेदार थीं या यह प्रक्रिया आणविक स्तर पर कैसे काम करती है।

50 साल पहले पहचानी गई यह घटना : वाइजमैन इंस्टीट्यूट के आणविक आनुवंशिकी विभाग के प्रोफेसर एली अरामा ने बताया कि जबकि यह घटना नई नहीं थी, कोशिकीय स्तर पर इस प्रक्रिया को देखना अभूतपूर्व था। यह घटना 50 साल पहले पहचानी गई थी। यह समझा गया था कि सभी कोशिकाएं विकिरण के बाद नहीं मरतीं। उन्होंने कहा कि कुछ जीवित रहती हैं, विभाजित होती हैं और ऊतकों का पुनर्निर्माण करती हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में इन कोशिकाओं को नहीं देख पाया, हम इन्हें पहली बार पहचानने में सफल रहे।

प्रतीकात्मक

24 घंटों में फिर बनने लगता है पूरा ऊतक : उन्नत आनुवंशिक उपकरणों और फल मक्खी के ऊतकों में जीवित ट्रैकिंग का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं की एक छोटी जनसंख्या का पता लगाया जो कोशिकीय आत्म विनाश कार्यक्रम, जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है, के प्रारंभिक चरणों को सक्रिय करती है, लेकिन फिर मरने से रुक जाती है। ये कोशिकाएं विकिरण को सहन करती हैं, तेजी से बढ़ती हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देती हैं।

अरामा ने कहा कि ये विकिरण के लगभग 24 घंटे बाद दिखाई देती हैं और अगले 24 घंटों में पूरा ऊतक फिर बनने लगता है। इस खोज के केंद्र में कैस्पेस हैं, जो ऐसे एंजाइम कोशिका हैं सेल डेथ करने के लिए जाने जाते हैं। इन फिर से बनने वाले कोशिकाओं में कैस्पेस सक्रिय होते हैं, लेकिन फिर नियंत्रित रहते हैं, जिससे कोशिकाएं जीवित रह सकती हैं, जबकि आसपास की कोशिकाओं में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले संकेतों को सक्रिय करती हैं।

यह संतुलन महत्वपूर्ण है। यह कैंसर उपचार में देखे गए एक चिंताजनक पैटर्न को समझाने में मदद कर सकता है। विकिरण चिकित्सा के बाद लौटने वाले ट्यूमर अक्सर अधिक आक्रामक और आगे के उपचार के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, वही जीवित रहने का तंत्र जो स्वस्थ ऊतकों को पुनर्जनित करने में सक्षम बनाता है, कैंसर कोशिकाओं द्वारा भी शोषित किया जा सकता है।

नई रणनीतियों का मार्गदर्शन : अरामा ने कहा कि कैंसर एक समान तंत्र का उपयोग करता प्रतीत होता है। अब जब हम समझते हैं कि ये कोशिकाएं जीवित रहने के लिए किस तंत्र का उपयोग करती हैं, तो हम इसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं कि वे जीवित न रहें। वाइजमैन इंस्टीट्यूट के एक बयान के अनुसार, कैंसर कोशिकाओं में जीवित रहने को चयनात्मक रूप से अवरुद्ध करने के तरीके सीखकर वैज्ञानिक विकिरण चिकित्सा के परिणामों में सुधार करने की आशा करते हैं।

अमेरिका में लांच की गई दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी

1954 में आज ही पहली परमाणु पनडुब्बी यूएसएस नाटिलस को अमेरिका में लांच किया गया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण यह महीनों तक पानी के नीचे रह सकती थी, जबकि डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों के इंजनों को भारी मात्रा में आक्सीजन की आवश्यकता होती थी।

पहली बार अमेरिका में मैग्नीशियम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ

1941 में आज ही टेक्सास के फ्रीपोर्ट में पहली बार मैग्नीशियम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ था। मैग्नीशियम को समुद्री जल से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता था। हर्बर्ट एच डो ने सबसे पहले 1916 में मिशिगन के मिडलैंड में खारे पानी से इस धातु को निकाला था।

भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है, वह केवल देशवासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भरोसे का केंद्र बन चुकी है। यहां की चिकित्सा सुविधाएं, किफायती दवाएं और दक्ष मानव संसाधन भारत को वैश्विक स्वास्थ्य मानचित्र पर अग्रणी बनाते हैं। आज भारत ऐसा देश है, जहां उच्च गुणवत्ता का इलाज आम नागरिक की पहुंच में है और यही स्वस्थ समाज की सबसे बड़ी पूंजी है।

– डा. देवी शेट्टी, प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ एवं संस्थापक, नारायण हेल्थ

केरल जल्द करेगा 'अपने' बैक्टीरिया की घोषणा

शाइन जेकब

आपने राज्य पशु, पक्षी या फूल के बारे में जरूर सुना होगा मगर अब केरल देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसका एक खास 'जीवाणु' (बैक्टीरिया) होगा। दरअसल राज्य के इस कदम का मकसद लोगों के बीच लाभकारी सूक्ष्मजीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका संरक्षण करना है।

इस बारे में एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि आगामी 23 जनवरी को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आधिकारिक तौर पर सबसे लाभकारी बैक्टीरिया में एक के नाम की घोषणा करेंगे जो कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों में मनुष्यों के लिए उपयोगी है। इतना ही नहीं, केरल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम (सीओईएम) जल्द ही खाद्य उत्पादों और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया सहित माइक्रोबायोम आधारित उत्पादों का विकास करेगा।

कई लोगों को राज्य 'बैक्टीरिया' सुनकर हैरानी हो सकती है। मगर राज्य के अधिकारियों का कहना है कि भारत के पास पहले से ही एक राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस है जिसका उपयोग दही के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसकी औपचारिक घोषणा 2012 में की गई थी।

केरल में शुक्रवार को सीओईएम के उद्‌घाटन के दौरान औपचारिक घोषणा की जाएगी। सीओईएम के निदेशक सबू थॉमस ने कहा, 'इस कदम का उद्देश्य लाभकारी बैक्टीरिया के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। हमारे पास राज्य पशुओं और पक्षियों के टैग हैं। हालांकि, सूक्ष्मजीवों की अदृश्य दुनिया प्रकृति में हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पूरे जीवन के लिए।' उन्होंने कहा कि यह कदम लोगों की यह मानसिकता बदलनी है कि बैक्टीरिया या वायरस केवल बीमारियां ही फैलाते हैं। राज्य ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए राज्य परिषद के तहत एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से इस बैक्टीरिया का चयन किया है। भारत में यह उद्योग अपने आप में छोटा नहीं है। होराइजन ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार भारत में समग्र माइक्रोबियल फर्मेंटेशन टेक्नॉलजी बाजार लगभग 4.47 अरब डॉलर का था और 2030 तक 8 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। यह एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, बायोलॉजिक्स और सक्रिय दवा तत्व (एपीआई) के उत्पादन के लिए जीवाणु किण्वन (बैक्टीरियल फर्मेंटेशन) के उपयोग के अलावा है। बैक्टीरिया का उपयोग औद्योगिक रूप से जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशक के लिए भी किया जाता है ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल फसल सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।

एक अन्य तेजी से बढ़ता इस्तेमाल प्रोबायोटिक का निर्माण है जिसका उपयोग बेहतर आंत स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादों के लिए किया जाता है। यह उद्योग मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस, बिफिदोबैक्टीरियम और बैसिलस स्ट्रेन पर निर्भर करता है। माइक्रोबायोम आधारित चिकित्सा भी तेजी से विकसित हो रही है जो किसी व्यक्ति के आंत में मौजूद बैक्टीरिया का विश्लेषण करती है। इसके जरिये हानिकारक रोगाणुओं को कम कस लाभकारी रोगाणुओं को बढ़ावा दिया जाता है। थॉमस ने कहा, 'मुख्य उद्देश्य न केवल एक बैक्टीरिया का संरक्षण करना है बल्कि कई का संरक्षण करना है। राज्य बैक्टीरिया का टैग केवल एक प्रतिनिधित्व होगा।' सीओईएण मनुष्यों, जानवरों, पर्यावरण और जलीय जीवन से संबंधित माइक्रोबायोम का व्यापक अध्ययन करेगा।

उन्होंने कहा, 'सीओईएम उद्योग के लिए माइक्रोबायोम आधारित उत्पादों को विकसित करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करना चाहता है। लिहाजा यह केवल एक शोध केंद्र नहीं होगा बल्कि इस तरह के उत्पादों की तकनीकी विशेषज्ञता उद्योग को हस्तांतरित करेगा।'

केंद्र का प्रमुख ध्यान अंतःविषय अनुसंधान और उद्यमिता, क्षेत्रों में परस्पर सहयोग और नवीन उत्पाद विकास का समन्वय करना है। यह माइक्रोबायोम डेटाबेस बनाने और स्टार्टअप तैयार करने के लिए बड़ी डेटा तकनीक और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके माइक्रोबायोम डेटा की मैपिंग भी करेगा।

सीओईएम को केरल सरकार द्वारा केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में केरल विकास और नवाचार रणनीतिक परिषद की साझेदारी और राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक मार्गदर्शन के साथ शुरू किया गया था। केंद्र का आदर्श वाक्य 'जीवन के लिए जीवाणु' है। केंद्र वर्तमान में किन्फ्रा फिल्म ऐंड वीडियो पार्क, कझाकूट्टम, तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसे स्थायी रूप से बायो 360 लाइफ साइंस पार्क तोन्नक्कल, तिरुवनंतपुरम में स्थानांतरित किया जाएगा।

दुनिया के 175 देशों के स्वास्थ्य की धड़कन बना भारत

स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि **वैश्विक नेतृत्वकर्ता** की भूमिका में भी, पहुंचा रहा है जरूरी दवाएं

सुनील शर्मा • जागरण

- एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब के रूप में पहचान बना चुका है हिमाचल का बद्दी
- देश की औषधीय शक्ति अपनी सीमाओं से परे मानवता की सेवा में लगी

बद्दी के प्रमुख फार्मा उद्योग

इन प्रमुख देशों को होती है दवाओं की आपूर्ति

वर्ष 2003 में विशेष औद्योगिक पैकेज से शुरू हुई यह यात्रा बीते दो दशकों में उस मुकाम तक पहुंची है, जहां लगभग प्रत्येक जरूरी दवा का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और भारत की औषधीय शक्ति अपनी सीमाओं से परे मानवता की सेवा में लगी है। बद्दी की यह कहानी केवल हिमाचल ... 'वसुधैव कुटुंबकम्' केवल विचार नहीं, बल्कि दवा की प्रत्येक शीशी में साकार होता है–जहां भारत का श्रम, विज्ञान और संकल्प दुनिया को स्वस्थ रखने में लगा है और यही तंत्र के गढ़ की असली पहचान है।

एक समय था जब उद्योगों को तकनीकी स्टाफ और श्रमिकों के लिए दूसरे राज्यों की ओर देखना पड़ता था और स्थानीय भागीदारी ... है। यह बदलाव केवल रोजगार का नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का संकेत है, जहां स्थानीय प्रतिभा वैश्विक जरूरतों को पूरा कर रही है। दवा उत्पादन के साथ-साथ प्रिंटिंग, पैकेजिंग और फायल निर्माण जैसे सहायक उद्योगों का प्रदेश में ही विकसित होना इस बात का प्रमाण है कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में ... भी गौरवपूर्ण है, क्योंकि यहां बनी दवाएं विकासशील ही नहीं, बल्कि विकसित देशों के स्वास्थ्य तंत्र का भी भरोसा हैं। सस्ती, प्रभावी और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरने वाली भारतीय दवाओं ने यह सिद्ध किया है कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य का संरक्षक है। जीएसटी लागू होने के बाद कर छूट समाप्त होने से कुछ ...

कच्चे माल का भी बड़ा वैश्विक केंद्र बनेगा: केंद्र और राज्य सरकारें दवा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खूब प्रयास कर रही हैं। यही वजह है कि कच्चे माल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी ठोस प्रयास हो रहे हैं। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए बल्क ड्रग पार्क की स्थापना और नीति समर्थन यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले ... उत्पादन का मात्र दो प्रतिशत कच्चा माल उपलब्ध हो, लेकिन अगले पांच वर्षों में देश में 60 प्रतिशत से अधिक कच्चा माल स्वदेशी होने की उम्मीद भारत के स्वास्थ्य भविष्य को और सुदृढ़ बनाती है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

बेहतर इलाज और कम लागत ने भारत को बनाया मेडिकल टूरिज्म का हब

पश्चिमी देशों की तुलना में कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वजह से भारत मेडिकल टूरिज्म के हब के तौर पर उभरा है। वर्तमान में भारत प्रौद्योगिकी में प्रगति, स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे के विस्तार और किफायती चिकित्सा देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उम्मीद है कि देश वर्ष 2026 के अंत तक 13 अरब डालर के साथ वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकेगा।

उन्नत स्वास्थ्य सेवा ढांचा

भारत अपनी स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में भारी निवेश कर रहा है, जिसमें अस्पतालों और विशेष चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की योजना है। 2030 तक, एआइ-आधारित निदान, रोबोटिक सर्जरी और टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकें विकसित होने की उम्मीद है जो इसे चिकित्सा पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाएगी।

उच्च कुशल चिकित्सा पेशेवर

भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित उच्च कुशल डाक्टरों, सर्जनों और चिकित्सा कर्मचारियों की प्रचुर संख्या है। कई भारतीय डाक्टरों ने भारत लौटने से पहले अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देशों में प्रशिक्षण और कार्य किया है, जिससे वे अपने साथ व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता लेकर आए हैं। 2030 तक, भारत में चिकित्सा पेशेवरों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है जिससे अंतरराष्ट्रीय मरीजों को और अधिक आकर्षित किया जा सकेगा।

आयुर्वेद व योग की समृद्ध विरासत

आयुर्वेद और योग की समृद्ध विरासत देश को स्वास्थ्य पर्यटन का अनूठा गंतव्य बनाती है। 2030 तक, भारत में स्वास्थ्य पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन का एकीकरण होने की संभावना है, जो एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा अनुभव प्रदान करेगा।

भारत में चिकित्सा पर्यटन

5 शीर्ष चिकित्सा पर्यटन स्थलों में शामिल है भारत दुनिया के

20 लाख से अधिक चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करता है प्रतिवर्ष

6 अरब डालर था देश के चिकित्सा पर्यटन बाजार का मूल्य 2022 में लगभग

13 अरब डालर तक पहुंचने की उम्मीद है 2026 तक चिकित्सा पर्यटन बाजार

70-80% तक कम है भारत में हार्ट सर्जरी, जोड़ों का प्रतिस्थापन व कास्मेटिक सर्जरी जैसी प्रक्रियाओं की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में

पिछले पांच वर्षों में इन देशों से इलाज कराने आए विदेशी पर्यटक

देश	2020	2021	2022	2023	2024
बांग्लादेश	99,155	1,86,633	3,26,805	4,99,951	4,82,336
इराक	16,647	15,357	30,701	28,758	32,008
सोमालिया	1,712	3,847	1,006	15,947	11,717
ओमान	4,328	7,610	11,121	13,397	10,431
उज्बेकिस्तान	1,712	3,847	6,768	7,081	8,921

हिंदुस्तान जिंक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ होगी चौथी तिमाही

हिंदुस्तान जिंक ने तीसरी तिमाही में चांदी के राजस्व में भारी उछाल और पांच वर्षों में अपनी सबसे कम लागत की मदद से अब तक का सबसे अधिक त्रैमासिक लाभ दर्ज किया। साकेत कुमार के साथ साक्षात्कार में कंपनी के सीईओ अरुण मिश्र ने लाभ की स्थिरता, चांदी व्यवसाय में विस्तार योजनाओं, लाभांश पर नजरिये और महत्त्वपूर्ण खनिजों में कंपनी के प्रवेश के बारे में विस्तार से बातचीत की। मुख्य अंश:

हिंदुस्तान जिंक ने पिछले पांच साल में जस्ता उत्पादन की सबसे कम लागत दर्ज की है। क्या आने वाली तिमाही में भी इतनी कम लागत को बनाए रखा जा सकता है?
हां, यह कमी ढांचागत रूप से टिकाऊ है। इसका एक मुख्य कारण कोयले और बिजली की कम लागत है। अब हम घरेलू कोयले का ...

... निकालने के लिए 200 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है। अगर इस पर उम्मीद के मुताबिक काम होता है, तो यह फ्यूमर रूट का विकल्प बन सकती है और आगे चलकर 30-35 टन और चांदी जोड़ सकती है।

आगे चलकर चांदी की कीमतों के संबंध में आपका क्या नजरिया है?
इस बारे में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। जनवरी में मुझे काफी भरोसा था कि चांदी 41 डॉलर तक पहुंचेगी और यह पहले ही उससे काफी आगे निकल चुकी है। आज के माहौल में, मैं कीमत का अंदाजा लगाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहूंगा।

नई शक्कर से बदलेगा मीठा खाने का तरीका

ऐसी शक्कर खोजी गई जो चीनी जैसी मीठी लेकिन कैलोरी कम

सेहत

92 फीसदी मीठास देता है टैगाटोज सामान्य चीनी की तुलना में

- वैज्ञानिकों ने कहा कि केवल एक तिहाई कैलोरी होती है
- यह खून में ग्लूकोज, इंसुलिन को तेजी से नहीं बढ़ाता

वॉशिंगटन, एजेंसी। मिठाइयों मिठाइयों के शौकीन लोगों के लिए राहत भरी खबर है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई शक्कर खोजी है, जो स्वाद में चीनी जैसी मीठी है, लेकिन इसमें कैलोरी बहुत कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह शरीर में इंसुलिन के स्तर को तेजी से नहीं बढ़ाती। इस खोज को सेहत के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है।

अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी और कुछ विज्ञान-कंपनियों ने बेहतर उत्पादन तरीका विकसित किया है। यह नई शक्कर प्राकृतिक है और इसका नाम 'टैगाटोज' है। यह कुछ फलों और दूध से बनने वाले उत्पादों में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब तक इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना मुश्किल था, क्योंकि इसका उत्पादन महंगा और जटिल था। इसी वजह से यह आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई।

वैज्ञानिकों ने अब टैगाटोज बनाने का एक नया और आसान तरीका खोज लिया है। इस नई तकनीक के जरिए साधारण ग्लूकोज को जैविक प्रक्रिया से टैगाटोज में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में खास तरह के एंजाइम और सूक्ष्म जीवों की मदद ली गई है, जिससे उत्पादन तेज, सस्ता और ज्यादा प्रभावी हो गया है।

टैगाटोज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खून में ग्लूकोज और इंसुलिन के स्तर को अचानक नहीं बढ़ाती। यही कारण है कि यह मधुमेह से पीड़ित लोगों और वजन नियंत्रित करने वालों के लिए बेहतर विकल्प मानी जा रही है। सामान्य चीनी जहां शरीर में तेजी से ऊर्जा बढ़ाकर नुकसान पहुंचा सकती है, वहीं टैगाटोज धीरे असर करती है।

यह बेकरी उत्पादों, मिठाइयों और पेय पदार्थों में आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है।

मिठाइयां बदल जाएंगी
वैज्ञानिकों का मानना है कि टैगाटोज जैसी शुगर से स्वस्थ मिठाइयां और ड्रिंक्स बनाना आसान होगा, वो भी बिना ब्लड शुगर या इंसुलिन में भारी वृद्धि के। इस तकनीक को औद्योगिक स्तर पर अपनाया जाता है, तो टैगाटोज का बाजार जल्दी बड़ा होगा।

ऐसे बनाया टैगाटोज
टफ्ट्स यूनिवर्सिटी और कुछ विज्ञान-कंपनियों ने उत्पादन तरीका विकसित किया है। उन्होंने एक आम बैक्टीरिया ईकोली को जैविक रूप से इस योग्य बनाया है कि वह ग्लूकोज को टैगाटोज में बदल दे। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है।

सबसे बड़ा हिमखंड टूट रहा, समुद्री आपदाओं का खतरा

बीजिंग, एजेंसी। चीन के फेंगयुन थ्री डी सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड ए23ए अब पूरी तरह टूटने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

इसके टूटे टुकड़े जब पिघलेंगे तो समुद्र का मीठा पानी बढ़ेगा। इससे समुद्री धाराएं बदल सकती हैं। मौसम प्रणालियों पर लंबे समय में असर पड़ सकता है। तापमान बदलने से पेंगुइन, सील जैसे जीवों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका तेजी से टूटने से समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। यह अंटार्कटिका में है। इसका मुख्य हिस्सा घटकर सिर्फ 506 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इसके टूटने की मुख्य वजह हाइड्रोफ्रैक्चरिंग है।

■ ऐसी स्थिति में समुद्र का जलस्तर बढ़ सकता है

गणतंत्र दिवस पर अत्याधुनिक इंतजाम

पहली बार कृत्रिम मेधा की मदद से यातायात प्रबंधन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

दिल्ली यातायात पुलिस ने गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर आवाजाही के आधुनिक इंतजाम किए हैं।

पहली बार कृत्रिम मेधा (एआइ) आधारित वीडियो के जरिए लोगों को पार्किंग और रास्तों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही समारोह के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार-कालिंग प्रणाली शुरू की गई है। इसकी मदद से लाउडस्पीकर के माध्यम से वाहनों को मौके पर बुलाया जाएगा।

गूगल मैप्स का भी सहारा लिया जा रहा है और सुरक्षाकर्मियों के लिए शटल सेवा भी ...

पार्किंग के लिए कुल 22 स्थान, आठ हजार वाहन होंगे खड़े

पुलिस ने बताया कि पार्किंग प्रबंधन प्रणाली में 22 पार्किंग स्थल शामिल हैं, जिनमें लगभग 8,000 वाहनों को खड़ा किया जा सकता है। पुलिस के अनुसार, हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए करीब 77,000 पास जारी किए जाते हैं, जिनमें से लगभग 8,000 पास निजी वाहनों से आने वालों के लिए निर्धारित होते हैं। इस वर्ष एक और नई पहल के तहत गणतंत्र दिवस ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए शटल सेवा शुरू की गई है। ...

हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब एआइ से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। हवाई अड्डे की सुरक्षा संभालने वाली एजंसी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) का कहना है कि नई तकनीक के प्रयोग से सुरक्षा जांच में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। सीआइएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने बताया कि आने वाले समय में हवाई अड्डा ...

समय से पहले ही खिल गया बुरांश का फूल, जलवायु परिवर्तन से बढ़ी चिंता

सुनील दत्त पांडेय

उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांश के अस्तित्व को बदलते पर्यावरण के कारण खतरा पैदा हो गया है, जिस वजह से उत्तराखंड के पर्यावरण के जानकार विशेषज्ञ बेहद चिंतित है। बुरांश जहां राज्य वृक्ष है वहीं यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए ...

जीव-जंतुओं पर विपरीत असर की आशंका

पक्षी विज्ञानी डाक्टर दिनेश चंद्र भट्ट का कहना है कि समय से पहले बुरांश के फूल खिलने से पक्षियों और जमीन पर रहने वाले छोटे जीव-जंतुओं पर भी इसका विपरीत असर पड़ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों के प्राकृतिक चक्र में बदलाव आने से जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। ...

बदलाव

मौसम का प्राकृतिक चक्र धीरे-धीरे बिगड़ रहा है। प्रोफेसर जोशी कहते हैं कि समय पर ठंड न पड़ना, बारिश-बर्फबारी का लगातार कम होना और तापमान का बढ़ना यहां की वनस्पतियों पर भी विपरीत प्रभाव डाल रहा है, जिस कारण उत्तराखंड के 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के वृक्षों में इस बार जनवरी में ही फूल खिलते हुए दिखाई देने लगे है जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है।

बुरांश के फूल लाल, गुलाबी और सफेद रंगों के होते हैं। उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन फूलों से शरबत और चटनी बनाई जाती है ...

BIHAR

Dainik Jagaran Page

Hindustan Page

'भारत के सुपर फाउंडर्स' में छाया बिहार का स्टार्टअप

पटना, वरीय संवाददाता। बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राज्य के स्टार्टअप 'डिजिटल लेबर चौक' को राष्ट्रीय उद्यमिता आधारित टेलीविजन कार्यक्रम 'भारत के सुपर फाउंडर्स' में फीचर किया गया है, जिसका प्रसारण अमेजन एमएक्स प्लेयर पर किया जा रहा है।

इस मंच पर स्टार्टअप को कुल ₹1.65 करोड़ की फंडिंग प्रतिबद्धता मिली है, जिसमें ₹65 लाख की इक्विटी और ₹1 करोड़ का अनुदान शामिल है। कार्यक्रम के दौरान थायरोकेयर के संस्थापक डॉ. वेलुमणि ने ₹1 करोड़ रुपये अनुदान देने की घोषणा की, जिससे असंगठित श्रम बाजार को औपचारिक स्वरूप देने की पहल को मजबूती मिली है। यह निवेश दैनिक

■ डिजिटल लेबर चौक को ₹1.65 करोड़ की फंडिंग

मजदूरों के लिए सम्मानजनक और पारदर्शी रोजगार उपलब्ध कराने के डिजिटल लेबर चौक के मिशन पर निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।

स्टार्टअप की विकास यात्रा में बिहार सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उद्योग विभाग की स्टार्टअप नीति के तहत इसे सीड फंडिंग, मैचिंग लोन, इनक्यूबेशन सुविधा और मेंटरशिप का लाभ मिला, जिससे इसका विस्तार हुआ। दरभंगा के गांव से आने वाले संस्थापक व सीईओ चंद्रशेखर मंडल द्वारा स्थापित यह मंच कोविड के दौरान विकसित हुआ। आज यह प्लेटफार्म दो लाख से अधिक श्रमिकों और हजारों ठेकेदारों को देशभर में जोड़ चुका है।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में सूबे को राष्ट्रीय सम्मान मिला

पटना, हिब्यू। डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में बिहार को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की समीक्षा बैठक के दौरान यह सम्मान दिया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, बिहार के राज्य मिशन निदेशक शशांक शेखर सिन्हा ने यह सम्मान प्राप्त किया।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रभावी और व्यापक रूप से लागू करने के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। बिहार ने एबीडीएम अंतर्गत स्कैन एंड शेयर में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कुल पांच

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य निदेशक शशांक शेखर को राष्ट्रीय पुरस्कार देतीं ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग।

करोड़ 21 लाख टोकन का निमार्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य में कुल छह करोड़ आठ लाख लोगों की आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाई गई है।

बिहार में नये नियोजित शहर स्थापित होंगे: नीतीश

समृद्धि यात्रा

गोपालगंज/पटना, हिटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में नये नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। सात निश्चय 3 में मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के तहत आधारभूत संरचनाओं को और बेहतर किया जाएगा। इसी क्रम में शहरों का विकास किया जाएगा और नये नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। सीएम मंगलवार को गोपालगंज जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरौली में समृद्धि यात्रा के तहत आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों में विकसित बिहार बनाने का विजन और रोडमैप प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर और

गोपालगंज को 316 करोड़ की सीएम ने दी सौगात

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौली का मंगलवार को निरीक्षण करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ हैं मंत्री विजय कुमार चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत।

प्रति व्यक्ति औसत आय को भी दोगुना किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में युवाओं को एक करोड़ रोजगार और नौकरियां उपलब्ध कराना है। इसके लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने जिला को 316 करोड़ की सौगात दी। 181 करोड़ की 33 योजनाओं का शिलान्यास किया जबकि 135 करोड़ की 7 योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 से 2030 के लिए सात निश्चय पार्ट-3 में रोजगार और आय दोगुना करने का संकल्प लिया गया है। समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। पांच वर्षों में सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। › देखें P 14

पांच नए एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण सड़कों का टू-लेन चौड़ीकरण होगा तथा पांच नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में पर्यटन और इको-टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी बनेगी और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सबका सम्मान-जीवन आसान के तहत तकनीक और सुशासन के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल बनाया जाएगा।

NATIONAL

Hindustan Page

Jansatta Page.

वैश्विक उथल-पुथल के दौर में सेनाओं को भविष्य के हथियारों से लैस करना जरूरी

बजट 2026-27 बिगुल

संजय मिश्र • जागरण

नई दिल्ली: देश का 2026-27 का आम बजट ऐसे समय में आने जा रहा जब वर्तमान वैश्विक व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर सुरक्षा और सैन्य खतरों से रूबरू हो रही है। उथल-पुथल के ऐसे दौर में भारत जैसी उभरती वैश्विक ताकत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा केवल अपनी सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं रह गई है। पड़ोसी देशों के साथ जटिल संबंधों और लंबी समुद्री सीमाएं भारत की बढ़ती रक्षा जरूरतों को अपरिहार्य बना रही हैं। युद्ध के बदलते स्वरूप तथा तीव्र आधुनिक टेक्नोलाजी पर आधारित हथियारों-उपकरणों ने देश की रक्षा चुनौतियां को बहुआयामी बना दिया है। ऐसे में तात्कालिक रक्षा उपकरणों-हथियारों की खरीद तथा तकनीकी अपग्रेडेशन ही इन बहुआयामी चुनौतियों का समाधान नहीं है बल्कि आधुनिकीकरण के साथ सेनाओं को नए दौर के वारफेयर से लैस करना जरूरी हो गया है।

आपरेशन सिंदूर, अमेरिका का ईरान पर हमला या फिर रूस-यूक्रेन तथा गाजा में इजरायल-हमास के ताजा युद्धों ने साबित किया है कि अब निर्णायक जंग आकाश में ही लड़ी जाएगी। चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास, आधुनिक हथियारों की तैनाती और साइबर व अंतरिक्ष वार फेयर क्षमताओं में निवेश तो दूसरी ओर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और छद्म युद्ध की रणनीति में अब ड्रोन-यूएवी तथा साइबर वार की चुनौतियां जटिलता बढ़ा रही हैं। हिंद महासागर समेत समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, रणनीतिक बंदरगाहों में निवेश और समुद्री मार्गों पर आधिपत्य स्थापित करने की उसकी कोशिशें भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभरी हैं। ऐसे में साफ है कि सेना, नौसेना और वायुसेना को इन चुनौतियों के लिहाज से आधुनिक बनाए जाने की जरूरत है।

युद्ध में बढ़ रही साइबर स्पेस, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक वार फेयर की भूमिका : भारत की सशस्त्र सेना संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल है, लेकिन आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के संदर्भ में कई स्तरों पर क्षमताओं का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। थल सेना को आधुनिक एयर डिफेंस, उन्नत टैंक और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणालियों की आवश्यकता है। वायुसेना लंबे समय से लड़ाकू विमानों के बेड़े में कमी से जूझ रही है। इस दिशा में 114 नए राफेल लड़ाकू जेट खरीदने की प्रक्रिया अब आगे बढ़ती दिख रही है। नौसेना के लिए जरूरी युद्धपोतों-पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजनाएं चल रही हैं मगर इन्हें गति देने की जरूरत है। आधुनिक युद्ध में साइबर स्पेस, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक वार फेयर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वचालित हथियार प्रणालियां युद्ध की प्रकृति को बदल रही हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में रक्षा बजट का पूंजीगत निवेश बढ़ाना जरूरी है ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके। तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण के लिए संयुक्त थिएटर कमांड बनाने की योजना को धरातल पर गति दिया जाना जरूरी है और अब इसे बजट तथा प्रशासनिक बाधाओं के दायरे से बाहर निकालना जरूरी है।

अमेरिका, चीन और रूस की तुलना में रक्षा पर खर्च बेहद कम

रक्षा पर खर्च करने वालों में भारत दुनिया के पांच देशों में शामिल है मगर फिर भी चीन, अमेरिका और रूस की तुलना में यह बेहद कम है। वर्ष 2025-26 बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपये रक्षा आवंटन था जो 2024-25 के मुकाबले करीब साढ़े नौ प्रतिशत अधिक था मगर इसमें पूंजीगत आवंटन की हिस्सेदारी 1.81 लाख करोड़ रुपये ही थी। पूंजीगत आवंटन के बारे में पूछे जाने पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि रक्षा खरीद की प्राथमिकताओं में फंड का कोई अवरोध नहीं आएगा सरकार ने इस बारे में सेनाओं को आश्वस्त किया है।

वेतन और पेंशन में जाता है रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा

रिटायर मेजर जनरल जेकेएस परिहार कहते हैं, 'स्वदेशी हथियारों की सबसे बड़ी परीक्षा उनकी समय पर उपलब्धता और कसौटी पर खरा उतरने की है। मौजूदा परिदृश्य में आत्मनिर्भरता की नीति और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को पाटना होगा। रक्षा पूंजीगत आवंटन में बड़ी वृद्धि इसके लिए जरूरी है क्योंकि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा वेतन-पेंशन में जाता है। रक्षा बजट में बेशक हर वर्ष बढ़ोतरी होती है मगर यह सालाना मुद्रास्फीति के समायोजन के आस-पास ही रहती है और सैन्य आधुनिकीकरण को जिस गति से बढ़ाना है उसके लिए यह आवंटन पर्याप्त नहीं होते।'

जीडीपी का कम से कम तीन प्रतिशत हो रक्षा बजट

सेनाओं के आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए मेजर जनरल परिहार कहते हैं कि रूस-यूक्रेन, इजरायल-हमास तथा आपरेशन सिंदूर से साफ है कि भविष्य में उच्च तीव्रता वाले छोटे युद्ध, मध्यम अवधि तथा लंबे समय तक चलने वाले युद्ध होंगे और इसके लिए सेनाओं को तैयार करना होगा। रक्षा बजट को जीडीपी के कम से कम तीन प्रतिशत के स्तर पर लाया जाए और राजस्व खर्च को पूंजीगत खर्च से अलग किया जाए। जाहिर तौर पर वित्तमंत्री से सेनाओं की अपेक्षा रहेगी कि देश की सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर रक्षा बजट का आवंटन निर्णायक रूप से बदलावकारी मार्ग की ओर ले जाए।

व्यवस्था

राष्ट्रीय विधायी सूचकांक से होगी विधानमंडलों की रैंकिंग

सम्मेलन में विधायी सुधारों पर व्यापक सहमति, तकनीक व जवाबदेही से मजबूत होगा लोकतंत्र, सत्रों की घटती संख्या, शोरगुल, एआइ उपयोग और विधायकों की क्षमता-वृद्धि पर गंभीर मंथन

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

देश की विधान सभाओं और विधान परिषदों को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई अहम निर्णयों और चिंतन बिंदुओं पर सहमति बनी। सम्मेलन का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (एनएलआइ) रहा, जिसके जरिये विधायिकाओं की प्रदर्शन आधारित रैंकिंग की जाएगी। इसके साथ ही सदनों की घटती बैठकों, बढ़ते हंगामे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के उपयोग और जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता-वृद्धि जैसे मुद्दों पर भी गंभीर विमर्श हुआ।

सम्मेलन के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि राष्ट्रीय विधायी सूचकांक को आकार देने के लिए इसी सम्मेलन में एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूचकांक से न केवल विधायिकाओं के कार्यों का आकलन होगा, बल्कि सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान भी हो सकेगी। सम्मेलन की मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानसभा कर रही है। बिरला ने कहा कि तकनीक, क्षमता-वृद्धि और गुणवत्ता के स्पष्ट मानकों से ही विधायिकाओं को नागरिक-केंद्रित और प्रभावी बनाया जा सकता है।

लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के मौके पर रविवार को ग्रुप फोटो के लिए जुटे माननीय। (एएनआइ)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि निगरानी के बिना नवाचार लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि विधायिका की जरूरतों के अनुरूप विशेष संसदीय एआइ टूल विकसित किए जाएं।

दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि यह सूचकांक विधायिकाओं को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाएगा और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। सम्मेलन में सुझाव दिया गया कि सदन के संचालन, प्रश्नकाल, विधायी कार्य, बजट पारित करने की समयसीमा, समितियों की सक्रियता और सदस्यों की भागीदारी जैसे मानकों को सूचकांक में शामिल किया जाए।

अनाज से अधिक फल व सब्जी पैदावार का क्षेत्र बढ़ा

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 20 जनवरी

भारत के कृषि क्षेत्र में दबे पांव कई बदलाव जारी है। यह क्रमिक रूप से जारी भी है। इस परिवर्तन में अनाज की तुलना में उच्च मूल्य वाले फलों व सब्जियों का रकबा बढ़ाना सबसे प्रमुख है।

आंकड़े दर्शाते हैं कि 2014-15 की तुलना में 2024-25 में बागवानी फसलों में विशेष तौर पर फल व सब्जी की पैदावार के क्षेत्र की सालाना चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) 1.66 प्रतिशत है जबकि अनाज की सीएजीआर 1.08 प्रतिशत है। बागवानी फसलों में सब्जियों का क्षेत्रफल अधिक तेजी से बढ़ा है। सब्जियों के रकबे का सीएजीआर 1.93 प्रतिशत है जबकि इस अवधि में फलों के रकबे का सीएजीआर 0.05 की दर से गिरा है। प्रतिशत के मामले में देखें तो यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। फलों का रकबा 2014-14 से 2024-25 के दौरान 17.35 प्रतिशत बढ़ा जबकि सब्जियों का प्रतिशत करीब 23 प्रतिशत था।

विविधीकरण

- **फलों का रकबा 2014-14 से 2024-25 के दौरान 17.35 प्रतिशत बढ़ा जबकि सब्जियों का करीब 23 प्रतिशत था**
- **बागवानी का कुल प्रतिशत 26 प्रतिशत था, अनाज का रकबा 10.45 प्रतिशत बढ़ा**

बागवानी का कुल प्रतिशत 26 प्रतिशत था। इसकी तुलना में अनाज का रकबा 10.45 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि 2019-20 से 2024-25 के बीच यह रुझान स्थिर रहा। वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान फलों के रकबे की सीएजीआर वृद्धि 1.15 प्रतिशत रही जबकि सब्जियों के लिए 2.56 प्रतिशत थी। इस अवधि में बागवानी फसलों की कुल वृद्धि 2.17 प्रतिशत थी जबकि यह अनाज के लिए 1.57 प्रतिशत थी। लिहाजा यह स्पष्ट है कि जब रकबे की वृद्धि का मामला आता है तो बागवानी फसलों - मुख्य तौर पर फल व सब्जी ने अनाजों को पछाड़ दिया है।

प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री व नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ के 24वें वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में शोध पत्र पेश किया था। इस शोधपत्र के अनुसार 2014-15 से 2023-24 के दौरान 2011-12 की कीमतों पर अनाज के उत्पादन मूल्य में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.36 प्रतिशत रही। हालांकि फलों में यह दर 3.68 प्रतिशत और सब्जियों में 2.77 प्रतिशत थी।

सेंट्रल रजिस्ट्री पर केंद्र को मिलेगा नियंत्रण!

हर्ष कुमार
नई दिल्ली, 20 जनवरी

केंद्र सरकार सरफेसी ऐक्ट 2002 में कुछ संशोधनों पर विचार कर रही है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इसका मकसद कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करना, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन ऐंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) की निगरानी मजबूत करना और कारोबार को सुगम बनाना है।

सिक्योरिटाइजेशन ऐंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल ऐसेट्स ऐंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सरफेसी) अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालत या ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बिना उधार लेने वाले या गारंटर की सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ सुरक्षा हितों को लागू करके 1 लाख रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए एक सक्षम कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

सीईआरएसएआई भारत सरकार द्वारा संपत्तियों पर सुरक्षा हितों (बंधक/शुल्क) को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया एक केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस है, जो अचल, चल और अमूर्त संपत्तियों के खिलाफ ऋणों का विवरण संग्रहीत करके धोखाधड़ी करके एक ही संपत्ति पर कई ऋणों को रोकता है, ऋण देने में पारदर्शिता बढ़ाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि ऋणदाता पूर्व देयताओं को सत्यापित कर सकें। प्रस्तावित बदलावों में से एक का मकसद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की शक्तियों को प्रभावित किए बगैर सीईआरएसएआई को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र को स्पष्ट रूप से सशक्त बनाना है। वर्तमान में सरफेसी अधिनियम की धारा 20 में केंद्र को सीईआरएसएआई स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन निर्देश जारी करने को लेकर शक्तियां स्पष्ट नहीं की गई हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'केंद्र सरकार की स्पष्ट रूप से परिभाषित शक्तियां न होने के कारण सेंट्रल रजिस्ट्री की निगरानी को लेकर इसके पहले कुछ मामलों में भ्रम पैदा हुआ।' अधिकारी ने आगे कहा, 'सीईआरएसएआई को अब क्रिटिकल इनफार्मेशन इन्फ्रा के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ ही केंद्र द्वारा निर्देश जारी कनरे के अधिकार को साफ करने से शासन और कामकाज में सुधार होगा।' अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों का व्यापक उद्देश्य सुरक्षा संबंधी हितों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना, लेनदारों के विश्वास को मजबूत करना और खासकर ऋण पाने के मानक को लेकर भारत की कारोबार सुगमता के संकेतकों में सुधार करना है।

सूत्रों में से एक ने कहा, 'इन परिवर्तनों का उद्देश्य सेंट्रल रजिस्ट्री के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करना और परिचालन अनिश्चितताओं को दूर करना है, जो समय के साथ उभरी हैं।' इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय को भेजे गए एक ईमेल का जवाब समाचार के प्रेस में जाने तक नहीं मिला।

केंद्र सरकार को अधिनियम के अध्याय 4 और अध्याय 4 ए दोनों के तहत सेंट्रल रजिस्ट्री से संबंधित अपनी शक्तियों को रिजर्व बैंक को सौंपने की अनुमति देने के लिए भी सरकार कानून में संशोधन का प्रस्ताव कर रही है।

इस समय धारा 20 आरबीआई को अध्याय 4 के तहत सेंट्रल रजिस्ट्री की स्थापना, संचालन और विनियमन के लिए शक्तियों की अनुमति देती है, लेकिन केंद्रीय बैंक ने बताया है कि उसके पास अध्याय 4 ए के तहत पेश किए गए कार्यों और दायित्वों पर नियामक शक्तियां नहीं हैं। 2016 में संशोधन कर डाले गए अध्याय 4 ए में सुरक्षित लेनदारों और अन्य लेनदारों द्वारा सुरक्षा हित बनाने वाले लेनदेन का पंजीकरण शामिल है। एक अधिकारी ने कहा, 'रिजर्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उसके पास अध्याय 4 ए के तहत परिकल्पित सेंट्रल रजिस्ट्री के कार्यों को विनियमित करने का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है। प्रस्तावित संशोधन से स्थिति को साफ करने की कवायद की गई है।'

एक अन्य प्रस्तावित स्पष्टीकरण सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ लेनदेन विवरण दाखिल करने से जुड़ा हुआ है। धारा 23 के तहत प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण या सुरक्षा हित के निर्माण से जुड़े सभी लेनदेन पंजीकृत होने चाहिए। हालांकि, पहले के संशोधनों की कुछ अदालती व्याख्याओं से इस बारे में अस्पष्टता पैदा हो गई है कि क्या विवरण दाखिल करने का दायित्व सुरक्षित लेनदार पर है।

सरकार अब यह स्पष्ट करने की योजना बना रही है कि अलग अलग मामलों के मुताबिक ऐसे विवरण दाखिल करने की जिम्मेदारी प्रतिभूतिकरण कंपनी, पुनर्निर्माण कंपनी या सुरक्षित लेनदार पर हो। सूत्र ने कहा, 'अनुपालन दायित्वों में निश्चितता लाने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए यह स्पष्टीकरण आवश्यक है।'

सरफेसी ऐक्ट में संशोधन पर विचार

- इसका मकसद कानूनी अस्पस्टताओं को दूर करना, सीईआरएसएआई की निगरानी मजबूत करना और कारोबार को सुगम बनाना
- इन बदलावों से केंद्र को सीईआरएसएआई को निर्देश जारी करने का स्पष्ट अधिकार मिल जाएगा
- लेनदेन विवरण दाखिल करने की जिम्मेदारी प्रतिभूतिकरण कंपनी, पुनर्निर्माण कंपनी या सुरक्षित लेनदार की हो सकती है

भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन आज से

नई दिल्ली, 20 जनवरी (ब्यूरो)।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन आज से 23 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य, भारत स्थित विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि, साथ ही शिक्षाविद और चुनावी क्षेत्र के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रियाओं के नवाचारों पर वैश्विक मंच प्रदान करेगा।

शुभारंभ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी द्वारा प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों का औपचारिक स्वागत कर किया जाएगा। इसके बाद उद्घाटन समारोह में वैश्विक नेतृत्व की झलक दिखेगी। कार्यक्रम में सामान्य और पूर्ण सत्रों के अलावा निर्वाचन प्रबंधन निकायों के प्रमुखों की बैठकें, कार्य-समूह चर्चाएं और वैश्विक चुनावी चुनौतियों, आदर्श चुनावी मानकों तथा नवाचारों व सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित विषयगत सत्र शामिल हैं।

Dainik Jagaran Page
Jansatta Page

INTERNATIONAL

भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की सोच को रूस का समर्थन

- रूस-भारत-चीन इस व्यवस्था को दे रहे आकार : लावरोव
- कहा, भारत और रूस का खास तरह का रणनीतिक संबंध

मास्को, प्रेट्र : रूस ने भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की सोच का समर्थन करते हुए कहा है कि रूस, भारत व चीन विश्व के ध्रुव हैं, ये विश्व में एकाधिकार वाली व्यवस्था खत्म करते हुए संतुलन कायम रखे हुए हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, रूस के भारत व चीन से शानदार द्विपक्षीय रिश्ते हैं।

लावरोव ने यह बात 2025 में रूसी कूटनीति के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कही। उन्होंने भारत के साथ रूस की रणनीतिक साझेदारी का प्रमुखता से जिक्र किया। कहा, इसी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया था। ज्ञात हो, पुतिन ने दिसंबर में भारत का दो दिनी दौरा किया था। इस दौरे में दोनों देशों ने आने वाले पांच वर्षों में आर्थिक साझेदारी को नए आयाम देने का समझौता किया है। लावरोव ने चीन के साथ संबंधों के स्तर को अप्रत्याशित बताया। कहा, ये इतनी गहराई तक हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। भारत-चीन के साथ रूस के संबंध विश्व में यूरेशिया के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक हैं।

लावरोव ने कहा, हमें रूस-भारत-चीन (आरआइसी) की परिकल्पना को मजबूत बनाने को और गति देने की जरूरत है। यह परिकल्पना 2020 में गलवन घाटी में हुए भारत-चीन टकराव की वजह से कई वर्षों के लिए नेपथ्य में चली गई थी। अतः इस त्रिपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। यह मजबूती ब्रिक्स के रूप में सामने आ रही है। यह संगठन बहुध्रुवीय व्यवस्था वाले विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका संस्थापक सदस्य हैं। बाद में ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई व सऊदी अरब भी इसमें शामिल हुए हैं।

भारत है निवेश के लिए अमेरिका के बाद सबसे पसंदीदा ठिकाना

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 20 जनवरी

अंतरराष्ट्रीय निवेश की योजना बना रहे मुख्य कार्याधिकारियों की नजर में भारत दूसरा सबसे पसंदीदा गंतव्य है। पिछले साल भारत पांचवें स्थान पर था। इस मामले में अमेरिका पहली पसंद बना हुआ है। मंगलवार को जारी पीडब्ल्यूसी के 29वें वार्षिक ग्लोबल सीईओ सर्वे में यह सामने आया है।

निवेश की योजना बना रहे सीईओ में से 35 प्रतिशत ने कहा कि वे अमेरिका में निवेश करना चाहेंगे, इसके बाद 13 प्रतिशत ने भारत, ब्रिटेन और जर्मनी को अपनी पसंद बताया। भारत के सीईओ देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर विदेशी सीईओ की तुलना में ज्यादा आशावादी हैं। भारत के 77 प्रतिशत सीईओ ने आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है,जबकि 55 प्रतिशत वैश्विक दिग्गजों ने सकारात्मक रुख दिखाया। सर्वे में दिखाया गया है कि 57 प्रतिशत भारतीय सीईओ निकट भविष्य में राजस्व वृद्धि को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन उन्होंने अगले 12 महीनों में वृहद आर्थिक अस्थिरता और साइबर जोखिमों को प्रमुख चुनौती बताया है।

वैश्विक स्तर पर भारत की सबसे बड़ी यूएसपी हैं प्रधानमंत्री मोदी : प्रल्हाद जोशी

दावोस,प्रेट्र: केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को कहा, वैश्विक कंपनियां भारत में स्थिर सरकार, स्पष्ट नीतियां व मजबूत प्रतिभा होने से भरोसा कर रही हैं। वैश्विक मंच पर पीएम मोदी भारत की सबसे बड़ी यूएसपी (विशिष्ट पहचान) हैं।

प्रल्हाद जोशी ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के दौरान कहा, दावोस में उनकी बैठकों के दौरान यह स्पष्ट नजर आया कि वैश्विक निवेशकों को भारतीय नेतृत्व पर भरोसा है। वे भारत को बढ़िया निवेश गंतव्य मानते हैं। कहा, 10–11 वर्ष पहले भारत को नाजुक अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था, अब वह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जहां देश को एक लाख करोड़ डालर से दो लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनने में 50 साल से ज्यादा समय लगा, वहीं चार लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनने में एक दशक लगा।

वैष्णव ने कहा, वैश्विक उद्योग भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखता है: एएनआइ के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है और वैश्विक उद्योग देश को विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में वैष्णव ने कहा, भारत डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग, सामग्री, गैसों व उपकरणों को शामिल करते हुए संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। गूगल भारत के एआइ इकोसिस्टम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है, जिसमें विशाखापत्तनम में 15 अरब अमेरिकी डालर का एआइ डेटा सेंटर और भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी शामिल है।

कंपनियों का भारत पर बड़ा दांव

एजेंसियां
दावोस, 20 जनवरी

देश-दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की वृद्धि को आशा की नजर से देख रही हैं और यहां बड़े निवेश करने के लिए योजनाएं बना रही हैं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के दौरान कई कंपनियों के प्रमुखों ने कहा कि रणनीतिक रूप से भारत बेहद महत्त्वपूर्ण बाजार है। यहां मंगलवार को कई कंपनियों ने जहां ऊर्जा, एआई समेत कई क्षेत्रों में करार किए।

मंगलवार को जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक परिदृश्य सुस्त रहने के बावजूद भारतीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अपने देश की अर्थव्यवस्था और अपनी कंपनियों की आय वृद्धि को लेकर अधिक आशावादी हैं। डब्ल्यूईएफ बैठक के दौरान जारी पीडब्ल्यूसी की वार्षिक सीईओ सर्वेक्षण रिपोर्ट में करीब 4,454 लोगों की राय ली गई, जिसमें लगभग 50 सीईओ शामिल हैं।

दावोस में डब्ल्यूईएफ बैठक से इतर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सिस्को के अध्यक्ष एवं मुख्य उत्पाद अधिकारी जीतू पटेल ने कहा कि कंपनी भारत को रणनीतिक रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण बाजार मानती है और वहां निवेश करना जारी रखेगी। इसी प्रकार पवन ऊर्जा के अग्रणी सुजलॉन एनर्जी के उपाध्यक्ष गिरीश तांती ने कहा कि भारत निर्यात के माध्यम से वैश्विक पवन ऊर्जा मांग का 10 प्रतिशत पूरा करने में सक्षम है। सुजलॉन ने अपने 30 वर्ष के अस्तित्व में एक लंबा सफर तय किया है। संस्थापक सदस्य के अनुसार अब कंपनी पवन ऊर्जा उत्पादन व्यवसाय के भीतर एवं उससे परे विस्तार के लिए अपनी विंड 2.0 और सुजलॉन 2.0 पहलों के साथ विकास के अपने अगले चरण के लिए तैयार है।

बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार की सराहना करते हुए हिताची इंडिया के चेयरमैन भरत कौशल ने कहा कि जापान के निवेश संकल्पों को अब तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी वजह से अब भारत और जापान के बीच सौदों का आकार भी काफी बड़ा हो रहा है।

स्विगी के फूड मार्केटप्लेस के सीईओ रोहित कपूर ने कहा कि कंपनी ने अभी तक भारत में 85-90 प्रतिशत बाजार में प्रवेश नहीं किया है। कंपनी की वैश्विक विस्तार की कोई योजना नहीं है, क्योंकि घर में ही विस्तार की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारी विकास के अवसर के प्रति आश्वस्त, स्वच्छ ऊर्जा प्रमुख रीन्यू के प्रमुख सुमंत सिन्हा ने कहा है कि उनका समूह स्मार्ट तरीके से विस्तार करेगा और लालची हुए बिना या एक ही बार में सब कुछ दृष्टिकोण अपनाए बिना आगे बढ़ेगा।

दावोस में केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू व अन्य

दावोस में निवेश अवसरों पर चर्चा

दावोस में मंगलवार को विभिन्न कारोबारी समूहों ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई। गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर राज्य में आईटी, आईटीईएस सेक्टर और मौजूदा प्रस्तावित डेटा सेंटर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में विस्तार से बातचीत की। एक अन्य बैठक में एवरस्टोन समूह के प्रेसिडेंट जयंत सिन्हा ने मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को अपने समूह की पोर्टफोलियो और निवेश प्राथमिकताओं से अवगत कराया और स्केलेबल प्लेटफॉर्म, दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि प्रकट की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह अमरावती को दुनिया का सबसे बेहतरीन एवं खूबसूरत शहर बनाएंगे और इस प्रयास में भागीदार बनने के लिए सभी का स्वागत है। कर्नाटक को भारत की आर्थिक वृद्धि की कहानी का मजबूत स्तंभ बताते हुए राज्य के वरिष्ठ मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी संघीय संरचना में निहित है और कर्नाटक सहकारी संघवाद का प्रमुख उदाहरण है।'

भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र 'गिफ्ट सिटी' के प्रमुख संजय कौल ने कहा कि वैश्विक कंपनियां इसे भारतीय बाजारों तक पहुंच का माध्यम एवं एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए आधार के रूप में देख रही हैं। कौल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में देश का वैश्विक वित्तीय लेनदेन का केंद्र बनना भी जरूरी है। कौल ने कहा, 'भारत को एक ऐसा मजबूत वित्तीय तंत्र चाहिए जहां भारत दुनिया से और दुनिया भारत से संवाद कर सके और 'गिफ्ट सिटी' इसी मकसद को पूरा करता है।'

महाराष्ट्र में लोढ़ा डेवलपर्स करेगी 1 लाख करोड़ निवेश

रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ डेटा सेंटर पार्क के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश हेतु प्रारंभिक समझौता किया है। कंपनी ने चार महीने पहले राज्य सरकार के साथ डेटा सेंटर विकसित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी ने एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच से इतर लोढ़ा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अभिषेक लोढ़ा ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 19 जनवरी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोढ़ा डेवलपर्स ने कहा, 'अतिरिक्त एक लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ, कुल प्रतिबद्धता 1.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।'

आंध्र और आरएमजेड में 10 अरब डॉलर की साझेदारी

आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को दावोस में आरएमजेड ग्रुप के साथ 10 अरब डॉलर की रणनीतिक निवेश साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर डिजिटल, मिश्रित उपयोग और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। प्रस्तावित साझेदारी के तहत आरएमजेड ग्रुप विशाखापत्तनम के कपुलुप्पाडा चरण-1 आईटी पार्क में एक वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) पार्क विकसित करने की योजना बना रहा है।

व्यापार करार के करीब भारत और ईयू: उर्सुला

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लिएन ने दावोस में कहा कि मुक्त व्यापार समझौता करीब 2 अरब लोगों का एक बाजार तैयार करेगा

एजेंसियां
नई दिल्ली, 20 जनवरी

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लिएन ने मंगलवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) अगले सप्ताह ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा करने वाले हैं। यह कदम करीब 200 करोड़ लोगों के बाजार को जोड़ते हुए वैश्विक जीडीपी के एक-चौथाई हिस्से को कवर करेगा। यूरोपीय संघ की प्रशासकीय इकाई यूरोपीय आयोग की प्रमुख लिएन ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में यह बात कही।

उर्सुला ने कहा कि भारत और ईयू के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का ऐलान एक ऐतिहासिक अवसर होगा और यूरोप को दुनिया के तेजी से बढ़ते एवं गतिशील बाजार के साथ पहले जुड़ने का लाभ मिलेगा। लिएन ने कहा, 'मैं भारत की यात्रा पर जा रही हूं। हालांकि अभी काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब हैं। कुछ लोगों ने तो इसे सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौता कहा है। यह एक ऐसा समझौता होगा जो करीब 200 करोड़ लोगों का एक बाजार तैयार करेगा और वैश्विक जीडीपी का करीब चौथाई हिस्सा होगा।'

लिएन यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा के साथ 25 से 27 जनवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगी। दोनों नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता का भी कार्यक्रम है। इस शिखर सम्मेलन में एफटीए के अलावा दोनों पक्षों ने रक्षा ढांचा समझौता और 2026-2030 के लिए रणनीतिक एजेंडा तैयार करने की भी योजना है। प्रस्तावित सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी (एसडीपी) दोनों पक्षों के बीच गहन रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सक्षम करेगी और भारतीय कंपनियों को ईयू के 'यूरोप के लिए सुरक्षा कार्रवाई' (सेफ) कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर देगी।

लिएन ने वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे ईयू की प्राथमिकता में हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप ने ऊर्जा, कच्चे माल, रक्षा एवं डिजिटल क्षेत्रों में तेजी से कदम उठाए हैं और अब स्थायी बदलाव को अपनाकर अवसर का लाभ उठाना होगा। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से ही रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों के बीच एफटीए पर पहली बार बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में रोक दी गई थी। जून 2022 में वार्ता फिर से बहाल हुई थी। दोनों पक्ष अब व्यापार, निवेश, रक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में व्यापक समझौते पर सहमति बनाने के अंतिम चरण में हैं। शीर्ष ईयू नेता ने विशेष रूप से ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के महत्त्व का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, 'चाहे व्यापार हो या व्यवसाय, पूंजी हो या ऊर्जा- यूरोप को तत्परता से इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। हमारी शुरुआती बात अच्छी है। हम पवन ऊर्जा से लेकर अगली पीढ़ी की बैटरी तक के क्षेत्रों में वैश्विक चैंपियन के घर हैं। एयरोस्पेस से लेकर औद्योगिक मशीनों तक जो चिप्स या उन्नत हथियार बनाने के लिए आवश्यक हैं। हमारी कंपनियां अमेरिकी समकक्षों के समान गति से एआई अपना रही हैं।'

उर्सुला ने रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों को ईयू की प्राथमिकता बताया

शुल्क की धमकी से ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल

यूरोपीय संघ की शीर्ष अधिकारी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष यूरोपीय संघ के सदस्य देशों पर नए शुल्क नहीं लगाने पर सहमति जताई थी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष लिएन ने कहा कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप द्वारा प्रस्तावित नए शुल्क खासतौर पर लंबे समय से सहयोगी रहे देशों के साथ एक गलती हैं। वह ट्रंप की उस घोषणा पर प्रतिक्रिया दे रही थीं कि फरवरी से उन 8 यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा, जिन्होंने डेनमार्क के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा करने के ट्रंप के आह्वान के बाद डेनमार्क का समर्थन किया है।

व्यापार, शुल्क युद्ध में किसी की जीत नहीं : चीन

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि उनका देश अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार और वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक विविधता लाना चाहता है। उन्होंने कहा, 'संरक्षणवाद के मौजूदा माहौल में भी हम मुक्त व्यापार की सफलता में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में अपने समझौतों के नेटवर्क का विस्तार करना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें समान स्तर पर बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। ये बातचीत ऐसी होनी चाहिए, जिसमें सभी पक्षों का लाभ हो।

बैठक में चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने कहा, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक सहयोग और संवाद की जरूरत है। व्यापार और शुल्क युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है। चीन दुनिया के लिए अपने दरवाजे और अधिक खोलेगा।' उन्होंने कहा कि देश विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में अपने बाजार का विस्तार करने की योजना बना रहा है। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहयोग और संवाद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'हालांकि आर्थिक वैश्वीकरण पूरी तरह दोषमुक्त नहीं है, लेकिन कोई भी देश इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता और वे खुद को अलग-थलग नहीं कर सकते।'

एआई का लक्ष्य जीवन को बेहतर बनाना हो

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला ने कहा कि एआई का लक्ष्य हर किसी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। इसमें शिक्षा से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता तक शामिल है। नडेला ने एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यदि एआई से जुड़ी सारी चर्चा केवल आपूर्ति पक्ष या तकनीकी कंपनियों पर ही केंद्रित रही, तो यह एक 'बुलबुला' साबित हो सकता है।

13 राज्यों वाला अमेरिका ऐसे बना 50 राज्यों वाला देश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं। हाल में उन्होंने उनके इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले यूरोप के देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका का आक्रामक विस्तारवादी रवैया नया नहीं है। पिछले करीब 200 वर्ष में अमेरिका ने इसी तरह की नीतियों से दूसरे देशों के क्षेत्रों को खरीदा या कब्जा किया और 13 राज्यों वाला अमेरिका 50 राज्यों वाला देश बन गया। आइये जानते हैं कि अमेरिका ने अपना क्षेत्रफल कैसे बढ़ाया।

यूरोपीय देशों ने अमेरिका को बनाया उपनिवेश

ये वो वक्त था, जब दुनियाभर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे-धीरे यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचने लगे थे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कालोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कालोनी बसा लीं। अमेरिका को हथियाने की इस होड़ में फ्रांस भी शामिल हो गया। 1700 तक आते-आते उस समय की इन तीन ताकतों ने अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिली-जुली आबादी अमेरिका जा बसी।

अमेरिका का नक्शा बदलने वाले पांच बड़े फैसले

दशकों की लड़ाई से मिली आजादी

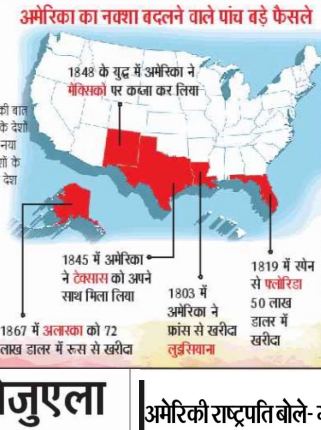

इनमें सबसे ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो, लेकिन ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आई। वहां आजादी की जंग शुरू हुई और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आजाद हो गया। 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में लागू हो गया। इसी वर्ष 30 अप्रैल को जार्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। चार जुलाई 1776 को आजादी के घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला।

विस्तारवादी बना अमेरिका

आजादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया, जो अब तक उसके साथ होता आया था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 तक अमेरिका ने 1.5 करोड़ डालर में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल तीन गुना तक बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका का मेक्सिको के साथ युद्ध शुरू हुआ। 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। मेक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए गए।

सेना भेज कर राज्यों पर किया कब्जा

अमेरिका धीरे-धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे-छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया।

इनमें इलिनोइस, ओहायो और फ्लोरिडा जैसे नाम शामिल थे। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहां वो अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका उदाहरण कैलिफोर्निया नरसंहार है, जहां अमेरिकी सरकार के इशारे पर हजारों लोगों को मार डाला गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे।

रूस से खरीदा अलास्का

अमेरिका ने 1867 में रूस से 72 लाख डालर में अलास्का को भी खरीद लिया. उसके बाद किंगडम ऑफ हवाई, प्यूर्टो रिको और गुआम पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर उसने स्पेन को दो करोड़ डालर देकर फिलीपींस खरीद लिया, लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आजादी मिल गई।

जागरण रिसर्च

ट्रंप ने कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिका में दिखाया

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया एआइ निर्मित 'नक्शा'

- कहा, ब्रिटेन का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया को छोड़ना मूर्खतापूर्ण
- यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति की विश्वसनीयता पर उठाया सवाल
- ट्रंप के रुख से वैश्विक शेयर बाजारों में हलचल, भारतीय बाजार भी लुढ़के

अमेरिकी नक्शे में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को सम्मिलित दिखाता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी एआइ निर्मित चित्र। इसमें ब्रिटिश पीएम कीएर स्टार्मर, इटली की पीएम जार्जिया मेलोनी, ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत अन्य बैठे दिखाए गए हैं। सौ. ट्रुथ सोशल

वाशिंगटन, एएनआइ : वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी को बंदी बनाने और डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने पर अड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रवैया जारी है। ट्रंप ने अब इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर एक एआइ निर्मित तस्वीर जारी की है। इसमें उन्होंने अमेरिकी मानचित्र में ग्रीनलैंड के साथ वेनेजुएला और कनाडा को भी अमेरिका के हिस्से के रूप में दिखाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति हिंद महासागर स्थित द्वीप डिएगो गार्सिया पर भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप ने सोमवार को अचानक ब्रिटेन द्वारा मारीशस को डिएगो गार्सिया द्वीप लौटाने पर सवाल उठा दिए। ब्रिटेन और मारीशस के बीच पिछले साल हुए इस समझौते का भारत के साथ-साथ अमेरिका ने भी समर्थन किया था। लेकिन अब ट्रंप का रुख बदल गया है। ट्रंप के नए आक्रामक रुख से वैश्विक शेयर बाजार में हलचल मच गई है और भारतीय शेयर बाजार भी लुढ़क गए हैं।

ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दो पोस्टों ने दुनिया में हलचल मचा दी। एक पोस्ट की एआइ तस्वीर में ट्रंप नाटो नेताओं के साथ अपने ओवल आफिस में बैठे दिख रहे हैं। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन और अन्य शामिल हैं। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं। इस एआइ तस्वीर में एक मील का पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, 'ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र। स्थापित 2026।' ट्रंप का यह रुख उनके पूर्व के बयानों से उलट है जिसमें उन्होंने मादुरो को बंदी बनाने के तुरंत बाद कहा था कि वेनेजुएला को अमेरिका तभी तक संभालेगा, जब तक वहां एक सुरक्षित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता। कनाडा के संबंध में ट्रंप ने पिछले वर्ष सुझाव दिया था कि वह अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चुनाव जीतने के बाद मई में अपनी पहली प्रेस कान्फ्रेंस में इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इच्छाओं और वास्तविकता के बीच फर्क किया जाना चाहिए। कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा।

एक अन्य पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चागोस द्वीप समूह मारीशस को सौंपने के ब्रिटेन की फैसले की भी आलोचना की। कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया को छोड़ना मूर्खतापूर्ण का काम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन और रूस ने इस कमजोरी पर ध्यान दिया है। ये दुनिया सिर्फ ताकत को पहचानती है, इसीलिए सिर्फ एक साल के उनके नेतृत्व में अमेरिका की इज्जत अब पहले से कहीं अधिक है। ब्रिटेन का इतनी जरूरी जमीन सौंपना बहुत बड़ी बेवकूफी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के उन कारणों से ग्रीनलैंड को हासिल करना जरूरी है। डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगियों को सही काम करना होगा।

रायटर के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड के बारे में मंगलवार को नाटो महासचिव मार्क रूट से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि वह दावोस में कई पार्टियों से मिलेंगे। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना रुख दोहराते हुए इसे अमेरिकी और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। इससे पहले ट्रंप ने डेनमार्क और ब्रिटेन समेत दूसरे यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई डील नहीं हुई तो एक फरवरी, 2026 से 10 प्रतिशत और एक जून, 2026 से 25 प्रतिशत टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने मंगलवार को ग्रीनलैंड को लेकर प्रस्तावित नए अमेरिकी टैरिफ को 'लंबे समय से सहयोगी देशों के बीच एक गलती' बताया और ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।

उर्सुला बोलीं, ट्रंप ने ईयू देशों पर और टैरिफ नहीं लगाने पर जताई थी सहमति पेज>>11

...तो फ्रांसीसी वाइन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी

वाशिंगटन: ट्रंप की ओर से गाजा युद्ध समेत वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थता के लिए शुरू की गई पहल 'बोर्ड आफ पीस' में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शामिल होने से कथित इन्कार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव किया है। अमेरिका फ्रेंच वाइन पर वर्तमान में 15 प्रतिशत टैरिफ लगता है। (पेज-11)

अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- ग्रीनलैंड पर अब पीछे हटने का सवाल नहीं, इस पर नाटो प्रमुख रूटे से बात हुई

ताकत के बल पर ही लाई जा सकती है शांति : डोनाल्ड ट्रंप

दो टूक

वाशिंगटन/लंदन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इस पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि ताकत के बल पर शांति कायम की जा सकती है और अमेरिका एक ताकतवर देश है।

ट्रंप ने कहा, इस मुद्दे पर नाटो प्रमुख मार्क रूटे से बात हुई है। मैं स्विट्जरलैंड के दावोस में अलग-अलग पार्टियों संग बैठक करने पर सहमत हूं। ट्रंप ने एक पोस्ट कर नाटो प्रमुख के चैट के स्क्रीनशॉट साझा किए, जिसमें रूटे अमेरिका के सीरिया और गाजा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, आपने सीरिया में जो किया वह अविश्वसनीय है। यह भी कहा कि मैं ग्रीनलैंड पर रास्ता खोजने के साथ आपसे मिलने को उत्सुक हूं।

दावोस बैठक में शामिल होंगे ट्रंप: ट्रंप ग्रीनलैंड मामले पर बुधवार-गुरुवार को दावोस में होने वाली अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। ट्रंप के दावोस बैठक में हिस्सा लेने से पहले यूरोपीय देश इस मंच पर जुटेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को 'ट्रुथ' पर यह एआई फोटो साझा करते हुए ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया। तस्वीर में ईयू देशों के नेता भी दिख रहे हैं।

ईयू अध्यक्ष ने टैरिफ की धमकी ट्रंप को चेताया

दावोस। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को टैरिफ की धमकी पर ट्रंप को चेताया। ट्रंप के कदम को गलत बताते हुए उन्होंने कहा, ऐसा कदम साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकता है। दावोस में उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और अमेरिका पिछले साल जुलाई में व्यापार समझौते पर सहमत हुए थे। डील, डील होती है। हम अमेरिकी लोगों को केवल सहयोगी, नहीं दोस्त भी मानते हैं। डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कहा कि ईयू दोनों देशों के लोगों के साथ खड़ा है।

'डिएगो गार्सिया द्वीप मॉरीशस को सौंपना मूर्खता'

लंदन, एजेंसी। ट्रंप ने डिएगो गार्सिया द्वीप को दोबारा मॉरीशस को सौंपे जाने के ब्रिटेन के फैसले की मंगलवार को निंदा की। कहा, यह अमेरिकी नौसैनिकों का मुख्य ठिकाना है।

ट्रंप ने ब्रिटेन के इस कदम को मूर्खतापूर्ण बताया। बोले, मैं इसलिए ग्रीनलैंड को कब्जे में लेना चाहता हूं। मैं हैरान हूं, ब्रिटेन अमेरिकी सैन्य अड्डे को मॉरीशस को देने की योजना बना रहा है।

मॉरिशस का द्वीप क्यों जरूरी

डिएगो गार्सिया द्वीप ऐसा आइलैंड है, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस है। ये पूर्वी अफ्रीकी तट से करीब 3,200 किमी दूर है। यहां दशकों से अमेरिका-ब्रिटेन का मिलिट्री बेस है, जिससे मिडिल ईस्ट से एशिया तक मिशन चलाने में आसानी होती है। ब्रिटेन ने 1965 में मॉरीशस से इन द्वीपों को अलग किया था, जो एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश था।

ग्रीनलैंड इसलिए अहम

ये आर्टिक व नॉर्थ अटलांटिक महासागर के करीब है, जिस वजह से सैन्य और सुरक्षा मामलों के लिहाज से अहम है। ट्रंप का मानना है, ग्रीनलैंड पर कब्जा होने से आसमान और समुद्र के साथ-साथ अंतरिक्ष से भी इस इलाके में दबदबा कायम होगा। यहां लिथियम के दुर्लभ भंडार भी हैं। तीसरा, यह एक प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग बन सकता है।

"ग्रीनलैंड-डेनमार्क की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। संघ नाटो देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। -उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय संघ प्रमुख

"यूरोपीय संघ को ट्रंप की टैरिफ धमकियों के सामने ट्रेड ब्लॉक के एंटी-कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से हिचकिचाना नहीं चाहिए। -इमैनुएल मैक्रों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति

"सहयोगी देशों द्वारा टैरिफ की धमकियां अस्वीकार्य हैं, जो नाटो संबंधों को कमजोर करती हैं और परेशानी को जन्म देती हैं। - अलेक्जेंडर स्टब, राष्ट्रपति फिनलैंड

"यूरोप के साथ अमेरिका के संबंध मजबूत हैं। ग्रीनलैंड को लेकर नई टैरिफ धमकियों से पैदा हुए तनाव को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। -स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी वित्त मंत्री

ग्रीनलैंड पर खुलते नए मोर्चे

ग्रीनलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। हालांकि, ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर हमला करने की हालिया धमकियां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से जुड़ी हैं, लेकिन यह डेनिश क्षेत्र लंबे समय से अमेरिकी हितों के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है।

पुष्परंजन

एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, जर्मनी के ज्यादातर लोग मानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां 'नाटो' को खतरे में डाल रही हैं। 'जेडडीएफ पालिटबैरोमीटर' सर्वे में शामिल लगभग 78 फीसद लोगों ने कहा कि ट्रंप का रवैया गठबंधन के लिए खतरा है, जबकि 18 फीसद लोग इससे सहमत नहीं थे। बाकी लोगों ने कहा कि वे पक्का नहीं कह सकते। यह सर्वे ऐसे समय में आया है, जब ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावों पर जोर दे रहे हैं, जो संसाधन से भरपूर आर्कटिक द्वीप है। नाटो सदस्य डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड , लेकिन उसे काफी आजादी मिली हुई है। इस मसले पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन का कहना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है, तो लंबे समय से चला आ रहा गठबंधन खत्म हो जाएगा। यह सवाल भी पूछा गया कि अगर अमेरिका आर्थिक संसाधनों को हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए दूसरे देशों में सैन्य हस्तक्षेप करता है, तो यूरोपीय संघ को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो 69 फीसद लोगों के स्पष्ट बहुमत ने कहा कि यूरोपीय संघ को ऐसे कामों का विरोध करना चाहिए। लगभग 22 फीसद लोगों का मानना है कि ब्रसेल्स को इससे दूर रहना चाहिए, जबकि सिर्फ पांच फीसद लोगों ने कहा कि यूरोपीय संघ को अमेरिका का साथ देना चाहिए।

क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रीनलैंड वृहदाकार है। हालांकि अमेरिका, रूस, कनाडा और चीन काफी बड़े हैं, लेकिन ग्रीनलैंड, जर्मनी से लगभग छह गुना बड़ा है। भारत को ग्रीनलैंड से डेढ़ गुना बड़ा माना जा सकता है, लेकिन मर्केटर प्रोजेक्शन वाले मानचित्रों पर ध्रुवों के करीब होने के कारण ग्रीनलैंड अक्सर भारत से बहुत बड़ा दिखता है। असल में, ग्रीनलैंड पूरे यूरोपीय संघ के आधे से ज्यादा आकार का है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि आस्ट्रेलिया, जिसे यह ताज मिलना चाहिए था, उसे एक महाद्वीप माना जाता है। ग्रीनलैंड के साथ भारत का रिश्ता मुख्य रूप से डेनमार्क के साथ उसकी मजबूत 'ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' यानी हरित रणनीतिक साझेदारी के जरिए आगे बढ़ता है, जो पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा और तकनीक पर केंद्रित है। आर्कटिक इलाके में भारत स्थिरता और शांतिपूर्ण बातचीत का समर्थन करता है।

सिर्फ़ 56,000 निवासियों के साथ ग्रीनलैंड धरती पर सबसे कम आबादी वाला इलाका माना गया है, जहां प्रति वर्ग किमी में लगभग 0.14 लोग रहते हैं। इसकी वजह ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति है। इस देश का 80 फीसद हिस्सा लगभग 30 लाख साल पहले बनी बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिससे बड़े इलाके रहने लायक नहीं हैं। 65 फीसद से ज्यादा आबादी ग्रीनलैंड की पांच नगरों में रहती है। नुक ग्रीनलैंड की राजधानी है। वहां केवल 19,905 लोग रहते हैं। सिसिमियुट (5,485), इलुलिसैट (5,087), काकोर्तोक (3,069) और आसियात में केवल 2,992 लोग रहते हैं। भारत के छोटे से छोटे कस्बे में इनसे कई गुना ज्यादा आबादी मिलेगी।

ग्रीनलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। हालांकि, ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर हमला करने की हालिया धमकियां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से जुड़ी हैं, लेकिन यह डेनिश क्षेत्र उससे कहीं ज्यादा समय से अमेरिकी हितों के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है। तत्कालीन अमेरिकी विदेश

मंत्री विलियम सेवर्ड ने 1867 में ही ग्रीनलैंड को अपने साथ मिलाने की बात की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रीनलैंड के सामरिक हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, ताकि यह नाजी जर्मनी के हाथों में न जाए। अमेरिका वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड के 'पिटुफिक स्पेस बेस'

> वर्ष 2025 में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वे में पाया गया कि द्वीप की बर्फ की चादर लगातार उनतीसवें साल भी सिकुड़ गई है। 'ग्रीनलैंड आइस शीट' ने हर साल लगभग 140 बिलियन टन बर्फ खो दी है। आर्कटिक बर्फ का पतला होना, इस इलाके में बढ़ती दिलचस्पी का एक और मुख्य कारण माना जाता है, खासकर अमेरिका की। ऐसा लगता है कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक उत्तर-पश्चिम गलियारा बनाएगा, जिसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों तक पहुंच के लिए रूस, चीन और दूसरे देशों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा।

का संचालन करता है, जिसे 1951 में अमेरिका और डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड रक्षा संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद बनाया गया था। साल 2023 में 'थुले एअर बेस' का नाम बदलकर 'पिटुफिक स्पेस बेस' कर दिया गया था।

चीन ने 2018 में आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के प्रयास में खुद को 'निकट-आर्कटिक राज्य' घोषित किया। आर्कटिक सर्कल भूमध्यरेखा से उत्तर में लगभग 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, जहां गर्मी के दिनों में चौबीस घंटे सूरज क्षितिज से नीचे नहीं डूबता और सर्दियों में चौबीस घंटे उदय नहीं होता। यह रेखा आठ देशों- कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका (अलास्का) के हिस्सों से होकर गुजरती है। इसके उत्तर का क्षेत्र 'आर्कटिक' कहलाता है।

वर्ष 2025 में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वे में पाया गया कि द्वीप की बर्फ की चादर लगातार उनतीसवें साल भी सिकुड़ गई है। 'ग्रीनलैंड आइस शीट' ने हर साल लगभग 140 बिलियन टन बर्फ खो दी है। आर्कटिक बर्फ का पतला होना, इस इलाके में बढ़ती दिलचस्पी का एक और मुख्य कारण माना जाता है, खासकर अमेरिका की। ऐसा लगता है कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक उत्तर-पश्चिम गलियारा बनाएगा, जिसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों तक पहुंच के लिए रूस, चीन और दूसरे देशों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। ग्रीनलैंड में यूरोपीय संघ यूनियन द्वारा जरूरी माने जाने वाले चौंतीस कच्चे माल में से कम से कम पच्चीस मौजूद हैं। हालांकि, इस इलाके में काफी मात्रा में लौह तत्त्व, ग्रेफाइट, टंगस्टन, पैलेडियम, वैनेडियम, जिंक, सोना, यूरेनियम, तांबा और तेल है, लेकिन सीमित बुनियादी ढांचे के कारण इनमें से ज्यादातर को निकालना मुश्किल है। ग्रीनलैंड के 'दुर्लभ खनिज' सबसे ज्यादा मांग वाली चीज है, जिस पर अमेरिका की गिद्ध दृष्टि लगी है।

हाल ही में आठ यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में कुछ सैनिक भेजने की हिम्मत की थी, पर ट्रंप द्वारा दस फीसद शुल्क दर लगाने की धमकी के बाद गुस्सा और बढ़ा है। ग्रीनलैंड समर्थक यूरोपीय देशों पर नए शुल्क लगाने की ट्रंप की धमकी के जवाब में यूरोपीय संघ अपने सबसे सख्त व्यापार नियम 'बजूका' पर विचार करने पर मजबूर हो गए हैं। यह कदम अमेरिकी सामानों और कंपनियों को यूरोपीय संघ के बाजार में पहुंच से रोक सकता है। हालांकि नाटो में पहले भी अमेरिका का विरोध होता रहा है, मगर बाद में 'सुलह' भी हो जाती है। दरअसल, अमेरिका में इस साल मध्यावधि चुनाव और घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की विफलता ने सारा गड्डमड्ड कर डाला है। उससे सबका ध्यान बंटे, इस वजह से ट्रंप कभी वेनेजुएला, तो कभी ईरान, गाजा, यूक्रेन के मुद्दे को पहाड़ की तरह उठा लेते हैं। ग्रीनलैंड भी ऐसे ही अभियान का हिस्सा है। हालांकि, इसका विरोध अमेरिका में ही शुरू हो चुका है।

अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप के आर्कटिक आइलैंड ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लाने की योजना की आलोचना की। अलास्का की रिपब्लिकन सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने अपनी डेमोक्रेटिक साथी न्यू हैम्पशायर की जीन शाहीन के साथ मिलकर एक विधेयक पेश किया है, जो किसी दूसरे नाटो सदस्य देश के इलाके पर एकतरफा कब्जा करने पर रोक लगाएगा। मुर्कोव्स्की ने कहा कि यह अब तक का सबसे सफल रक्षा समझौता है, जिसे ट्रंप बाधित कर रहे हैं। यों, 'यूनिटी प्रोटेक्शन बिल' सीनेट और उसके बाद प्रतिनिधि सभा में बहुमत के साथ पास होने की उम्मीद कम है। बहुमत का मतलब ट्रंप के विरुद्ध खुली बगावत होगा। जल्दी ही डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन वाशिंगटन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेशमंत्री मार्को रुबियो से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावों पर बात करने के लिए मिलेंगे। लेकिन लगता नहीं कि ट्रंप इतनी जल्द पीछे हटेंगे। ग्रीनलैंड अमेरिकी कूटनीति का 'हरि अनंत हरि कथा अनंता' बन चुका है!

EDITORIAL

Jansatta Page
Dainik Jagaran Page

डा. मोनिका राज
शोधार्थी

भारत-जर्मनी संबंध

बदलती विश्व व्यवस्था का नया सेतु

आज के अस्थिर समय में राष्ट्रों को अपनी पुरानी धारणाओं पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है और ऐसे नए साझेदार तलाशने पड़ रहे हैं, जो निर्भरता नहीं, बल्कि लचीलापन और संतुलन प्रदान कर सकें। इसी संदर्भ में भारत और जर्मनी के बीच बढ़ता हुआ सामरिक सामंजस्य विशेष महत्व रखता है। यह केवल एक द्विपक्षीय संबंध नहीं रह गया है, बल्कि एक व्यापक इंडो-यूरोपीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। भारत-जर्मनी यह समझने लगे हैं कि 21वीं सदी में स्थिरता किसी एक शक्ति या गुट के भरोसे सुनिश्चित नहीं की जा सकती

विश्व को नया संदेश दे गई जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा। फाइल

शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद के सबसे अशांत दौर से गुजर रही है। जिन आधारों पर वैश्विक राजनीति लंबे समय तक टिकी रही, अमेरिकी वर्चस्व, स्थिर सैन्य गठबंधन, पूर्वानुमेय व्यापार व्यवस्था और सुरक्षा के सर्वमान्य नियम, वे अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अंड्रियल रवैया, अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता का तीव्र होना, व्यापार और तकनीक का रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का बिखंडन, इन सभी ने मिलकर दुनिया भर में रणनीतिक अनिश्चितता का वातावरण बना दिया है। ऐसे अस्थिर समय में राष्ट्रों को अपनी पुरानी धारणाओं पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है और ऐसे नए साझेदार तलाशने पड़ रहे हैं, जो निर्भरता नहीं, बल्कि लचीलापन और संतुलन प्रदान कर सकें। इसी संदर्भ में भारत और जर्मनी के बीच बढ़ता हुआ सामरिक सामंजस्य विशेष महत्व रखता है। यह केवल एक द्विपक्षीय संबंध नहीं रह गया है, बल्कि एक व्यापक इंडो-यूरोपीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उभरती हुई रक्षा ताकत है, तथा भारत, जो जनसांख्यिकीय शक्ति और रणनीतिक स्वायत्तता के साथ एक उदीयमान वैश्विक शक्ति है-दोनों यह समझने लगे हैं कि 21वीं सदी में स्थिरता किसी एक शक्ति या गुट के भरोसे सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए विविधतापूर्ण साझेदारियों की जरूरत है, जो आर्थिक क्षमता, तकनीकी दक्षता, राजनीतिक बहुलता और रणनीतिक संतुलन को एक साथ जोड़ सकें।

द्विपक्षीय संबंधों से सामरिक भूगोल तक : भारत-जर्मनी संबंध सौहार्दपूर्ण तो रहे, परंतु उनमें एक प्रकार की सावधानी भी बनी रही। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी की विदेश नीति अटलांटिक गठबंधन में गहराई से जुड़ी हुई थी, जबकि भारत ने गुटनिरपेक्षता और बाद में रणनीतिक स्वायत्तता का मार्ग अपनाया। आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्कों के बावजूद इन संबंधों को लंबे समय तक कोई व्यापक धु-राजनीतिक ढांचा नहीं मिल सका। किंतु पिछले एक दशक की वैश्विक घटनाओं ब्रेक्जिट, ट्रंप काल की अमेरिकी नीतियां, यूक्रेन युद्ध और चीन की बढ़ती आक्रामकता ने जर्मनी के रणनीतिक सोच को गहराई से बदल दिया है। यूक्रेन युद्ध ने उसे रूसी ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता, रक्षा क्षेत्र में कम निवेश और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर जरूरत से ज्यादा भरोसे की वास्तविक कीमत समझा दी है। दूसरी ओर, भारत भी गंभीर सामरिक दबावों का सामना कर रहा है, जैसे कि चीन के साथ सीमा तनाव, पड़ोस में अस्थिरता और वैश्विक व्यापार व्यवस्था की अनिश्चितता। इन समानांतर चुनौतियों ने दोनों देशों को अपने पारंपरिक दायरों से बाहर निकलकर गहरे रणनीतिक सहयोग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अब जर्मनी भारत को केवल एक बाजार या विकासशील साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि यूरेशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का केंद्रीय स्तंभ मानने लगा है। भारत के लिए जर्मनी यूरोप की औद्योगिक प्रणाली, तकनीकी विशेषता और उभरती सुरक्षा ताकत तक पहुंच का प्रवेशद्वार है। इस प्रकार दोनों देश मिलकर यूरोप और हिंद-प्रशांत को जोड़ने वाले ऐसे सामरिक क्षेत्र की कल्पना कर रहे हैं, जो पारंपरिक सैन्य गठबंधनों से परे हो।

डी-रिस्किंग के युग में आर्थिक परस्परनिर्भरता : भारत-जर्मनी संबंधों की रीढ़ आर्थिक सहयोग है, किंतु वैश्विक परिस्थितियों के बदलने के साथ इसका स्वरूप भी बदल रहा है। जर्मनी आज भी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और द्विपक्षीय व्यापार लगातार नए स्तर छू रहा है। फिर भी अब इस रिश्ते को केवल व्यापार के आंकड़ों से नहीं आंका जाता। इसके केंद्र में आपूर्ति-श्रृंखला की मजबूती, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक विविधीकरण आ गया है। जर्मनी का औद्योगिक माडल, जो लंबे समय तक रूसी ऊर्जा और चीनी बाजारों पर निर्भर रहा, हाल के वर्षों में गंभीर दबाव में आया है। यह समझ उभरकर सामने आई है कि केवल आर्थिक दक्षता, यदि रणनीतिक दूरदृष्टि के बिना हो, तो वह राष्ट्रीय कमजोरियों को जन्म दे सकती है। इसी कारण जर्मनी ने 'डिकप्लिंग' के बजाय 'डी-रिस्किंग' की नीति अपनाई है। इस नए सोच में भारत एक स्वाभाविक साझेदार के रूप में उभरता है, अपने विशाल घरेलू बाजार, विस्तारित विनिर्माण आधार और उत्पादन-प्रोत्साहन जैसी नीतियों के कारण। भारत के लिए जर्मन निवेश केवल पूंजी नहीं लाता, बल्कि उन्नत विनिर्माण तकनीक, कौशल-प्रशिक्षण के माडल और उच्च पर्यावरणीय मानक भी साथ लाता है। भारत की विकास आकांक्षाएं और जर्मनी की विविधीकरण की आवश्यकता एक-दूसरे को मजबूती देती हैं। यह आर्थिक साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन को भी स्थिर और बहुध्रुवीय बनाने में योगदान देती है।

नई रणनीतिक यथार्थता : भारत-जर्मनी संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दिखाई देता है। जर्मनी द्वारा रक्षा बजट में वृद्धि एक निर्णायक मोड़ है। इससे भारत के साथ रक्षा सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं, जो अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और पुराने आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटा रहा है। यह सहयोग किसी सैन्य साझा अस्थिरताओं, अंतरराष्ट्रीय नियमों के क्षरण को लेकर व्यावहारिक साझेदारी के रूप में विकसित हो रहा है। रक्षा औद्योगिक सहयोग, सह-विकास और सह-उत्पादन के रोडमैप इसे रेखांकित करते हैं कि आज सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता और औद्योगिक मजबूती से जुड़ी है। भारत को इससे उच्च गुणवत्ता वाली रक्षा तकनीक और घरेलू रक्षा उद्योग को सशक्त बनाने का अवसर मिलता है, जबकि जर्मनी को पारंपरिक गठबंधनों से बाहर एक ऐसा साझेदार मिलता है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सहयोग यूरोप के उस नए सोच को भी दर्शाता है, जिसमें भारत को एक सक्रिय सुरक्षा भागीदार के रूप में देखा जाने लगा है।

इंडो-यूरोप की अवधारणा : 'इंडो-यूरोप' कोई औपचारिक संस्था नहीं, बल्कि एक उभरती हुई सामरिक कल्पना है। इसका उद्देश्य यूरोप के अटलांटिक-केंद्रित सोच को हिंद-प्रशांत की वास्तविकताओं से जोड़ना है। यह स्वीकार करता है कि एशिया में होने वाले आर्थिक और सुरक्षा संबंधी घटनाक्रम सीधे यूरोप के हितों को प्रभावित करते हैं। भारत इस अवधारणा का केंद्र इसलिए है, क्योंकि वह किसी कठोर सैन्य गुट में बंधे बिना विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने की क्षमता रखता है। यह न तो नाटो जैसा सैन्य गठबंधन है और न ही क्वाड जैसा ढांचा। इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थान है, और यह समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति-श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी शासन जैसे साझा मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देता है।

तकनीक, जलवायु और भविष्य : भविष्य की भारत-जर्मनी साझेदारी का केंद्रबिंदु तकनीक और जलवायु कार्रवाई बनने जा रहा है, क्योंकि यही वे क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के हित और क्षमताएं स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे से जुड़ती हैं। जर्मनी को नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और औद्योगिक डी-कार्बनाइजेशन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी माना जाता है, जबकि भारत सतत विकास और हरित परिवर्तन को अपनी विकास रणनीति का अनिवार्य हिस्सा बन रहा है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे क्षेत्रों में जर्मनी का तकनीकी अनुभव भारत की विशाल आवश्यकताओं और संभावनाओं के साथ मिलकर ठोस परिणाम दे सकता है। यह सहयोग केवल द्विपक्षीय लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक समाधान और मानक तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार, तकनीक और जलवायु पर आधारित यह साझेदारी भविष्य की विश्व व्यवस्था में भारत और जर्मनी को जिम्मेदार और दूरदर्शी साझेदार के रूप में स्थापित करेगी।

रिश्ते को मजबूती देते मानवीय संपर्क

भारत-जर्मनी के सामरिक दृष्टिकोणों में पूर्ण समानता न होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा प्राथमिकताएं भिन्न रही हैं। इन भिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद यह उल्लेखनीय है कि भारत-जर्मनी संबंधों में किसी प्रकार की दरार नहीं आई है, बल्कि यह स्थिति दोनों देशों के रिश्तों की परिपक्वता और व्यावहारिकता को दर्शाती है। जर्मनी यह समझने लगा है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता उसकी विदेश नीति का मूल आधार है और उससे किसी एक पक्ष में खड़े होने की अपेक्षा करना यथार्थवादी नहीं होगा। वहीं भारत भी यूरोप की सुरक्षा चिंताओं और जर्मनी की ऐतिहासिक संवेदनशीलताओं को समझते हुए संवाद बनाए रखता है। यही पारस्परिक समझ और मतभेदों के बावजूद सहयोग की क्षमता इस साझेदारी की वास्तविक शक्ति है, जो इसे एक बदलती और बहुध्रुवीय दुनिया में टिकाऊ बनाती है।

धु-राजनीति और अर्थव्यवस्था से परे, भारत-जर्मनी संबंध मानवीय संपर्कों से भी गहराते हैं। जर्मनी भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन रहा है। इससे न केवल जर्मनी की कौशल-आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। साथ ही प्रवासी समुदाय से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दे याद दिलाते हैं कि रणनीतिक साझेदारी केवल सरकारों के बीच नहीं, बल्कि समाजों के बीच विश्वास पर भी निर्भर करती है। भारत-जर्मनी के बीच बढ़ता सहयोग वैश्विक राजनीति में हो रहे व्यापक बदलावों का प्रतीक है। यह दिखाता है कि अस्थिरता के दौर में स्थिरता प्रभुत्व से नहीं, बल्कि विविध साझेदारियों से आती है।

-डा. मोनिका राज

दावोस में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा | बैठक | दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक सुर से सराहा

भारत सोई हुई ताकत, बन सकता है शीर्ष अर्थव्यवस्था

दावोस, 20 जनवरी (भाषा)।

वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में एक सुर से भारत की आर्थिक वृद्धि और निवेश संभावनाओं की सराहना की। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए दावोस पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत पहले से ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले दो-तीन वर्ष में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर 2048 तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व सरमा ने कहा कि उनका राज्य देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि असम का समय आ गया है और सभी निवेशकों को राज्य के विकास में भागीदार बनना चाहिए। शर्मा ने कहा, 'मैं यहां पहली बार आया हूं और मुझे लगता है कि हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था।'

नायडू ने 'इंडिया पैवेलियन' के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, 'हम दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत एक सोई हुई ताकत है और अगर हम जाग गए तो 2047 तक नंबर एक बन जाएंगे।' असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने कहा कि उनका राज्य 'एक्ट ईस्ट' और अन्य नीतियों से लाभान्वित हो रहा है।

उन्होंने अन्य सभी राज्यों को निवेश आकर्षित करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्य में प्रचलित पारंपरिक अभिवादन 'जोहार' से सभी का अभिवादन किया और सभी राज्यों को बधाई देते हुए उनकी सफलता की कामना की। सोरेन ने कहा कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। इंडिया पैवेलियन के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के अलावा, 10 राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। दावोस में भारत का यह सबसे बड़ा और सबसे विविध राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। इसमें शामिल नेता विभिन्न दलों से ताल्लुक रखने के बावजूद वैश्विक मंच पर भारत की एकजुट तस्वीर पेश कर रहे हैं।

इस मौके पर केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हुई, तब भारत ने रफ्तार पकड़ी और यह वृद्धि पथ अब भी निरंतर जारी है। उन्होंने दावोस में विभिन्न राज्यों की उपस्थिति की सराहना की और कहा कि जब कोई राज्य वृद्धि करता है तो देश भी वृद्धि करता है। जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत की वृद्धि गाथा के बारे में पूरी दुनिया को सूचित करना चाहिए।

कंपनियों का भारत पर बड़ा दांव

एजेंसियां
दावोस, 20 जनवरी

देश-दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की वृद्धि को आशा की नजर से देख रही हैं और यहां बड़े निवेश करने के लिए योजनाएं बना रही हैं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के दौरान कई कंपनियों के प्रमुखों ने कहा कि रणनीतिक रूप से भारत बेहद महत्त्वपूर्ण बाजार है। यहां मंगलवार को कई कंपनियों ने जहां ऊर्जा, एआई समेत कई क्षेत्रों में करार किए।

मंगलवार को जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक परिदृश्य सुस्त रहने के बावजूद भारतीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अपने देश की अर्थव्यवस्था और अपनी कंपनियों की आय वृद्धि को लेकर अधिक आशावादी हैं। डब्ल्यूईएफ बैठक के दौरान जारी पीडब्ल्यूसी की वार्षिक सीईओ सर्वेक्षण रिपोर्ट में करीब 4,454 लोगों की राय ली गई, जिसमें लगभग 50 सीईओ शामिल हैं।

दावोस में डब्ल्यूईएफ बैठक से इतर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सिस्को के अध्यक्ष एवं मुख्य उत्पाद अधिकारी जीतू पटेल ने कहा कि कंपनी भारत को रणनीतिक रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण बाजार मानती है और वहां निवेश करना जारी रखेगी। इसी प्रकार पवन ऊर्जा के अग्रणी सुजलॉन एनर्जी के उपाध्यक्ष गिरीश तांती ने कहा कि भारत निर्यात के माध्यम से वैश्विक पवन ऊर्जा मांग का 10 प्रतिशत पूरा करने में सक्षम है। सुजलॉन ने अपने 30 वर्ष के अस्तित्व में एक लंबा सफर तय किया है। संस्थापक सदस्य के अनुसार अब कंपनी पवन ऊर्जा उत्पादन व्यवसाय के भीतर एवं उससे परे विस्तार के लिए अपनी विंड 2.0 और सुजलॉन 2.0 पहलों के साथ विकास के अपने अगले चरण के लिए तैयार है।

बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार की सराहना करते हुए हिताची इंडिया के चेयरमैन भरत कौशल ने कहा कि जापान के निवेश संकल्पों को अब तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी वजह से अब भारत और जापान के बीच सौदों का आकार भी काफी बड़ा हो रहा है।

स्विगी के फूड मार्केटप्लेस के सीईओ रोहित कपूर ने कहा कि कंपनी ने अभी तक भारत में 85-90 प्रतिशत बाजार में प्रवेश नहीं किया है। कंपनी की वैश्विक विस्तार की कोई योजना नहीं है, क्योंकि घर में ही विस्तार की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारी विकास के अवसर के प्रति आश्वस्त, स्वच्छ ऊर्जा प्रमुख रीन्यू के प्रमुख सुमंत सिन्हा ने कहा है कि उनका समूह स्मार्ट तरीके से विस्तार करेगा और लालची हुए बिना या एक ही बार में सब कुछ दृष्टिकोण अपनाए बिना आगे बढ़ेगा।

दावोस में केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू व अन्य

दावोस में निवेश अवसरों पर चर्चा

दावोस में मंगलवार को विभिन्न कारोबारी समूहों ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई। गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर राज्य में आईटी, आईटीईएस सेक्टर और मौजूदा प्रस्तावित डेटा सेंटर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में विस्तार से बातचीत की। एक अन्य बैठक में एवरस्टोन समूह के प्रेसिडेंट जयंत सिन्हा ने मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को अपने समूह की पोर्टफोलियो और निवेश प्राथमिकताओं से अवगत कराया और स्केलेबल प्लेटफॉर्म, दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि प्रकट की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह अमरावती को दुनिया का सबसे बेहतरीन एवं खूबसूरत शहर बनाएंगे और इस प्रयास में भागीदार बनने के लिए सभी का स्वागत है। कर्नाटक को भारत की आर्थिक वृद्धि की कहानी का मजबूत स्तंभ बताते हुए राज्य के वरिष्ठ मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी संघीय संरचना में निहित है और कर्नाटक सहकारी संघवाद का प्रमुख उदाहरण है।'

भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र 'गिफ्ट सिटी' के प्रमुख संजय कौल ने कहा कि वैश्विक कंपनियां इसे भारतीय बाजारों तक पहुंच का माध्यम एवं एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए आधार के रूप में देख रही हैं। कौल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में देश का वैश्विक वित्तीय लेनदेन का केंद्र बनना भी जरूरी है। कौल ने कहा, 'भारत को एक ऐसा मजबूत वित्तीय तंत्र चाहिए जहां भारत दुनिया से और दुनिया भारत से संवाद कर सके और 'गिफ्ट सिटी' इसी मकसद को पूरा करता है।'

महाराष्ट्र में लोढ़ा डेवलपर्स करेगी 1 लाख करोड़ निवेश

रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ डेटा सेंटर पार्क के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश हेतु प्रारंभिक समझौता किया है। कंपनी ने चार महीने पहले राज्य सरकार के साथ डेटा सेंटर विकसित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी ने एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच से इतर लोढ़ा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अभिषेक लोढ़ा ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 19 जनवरी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोढ़ा डेवलपर्स ने कहा, 'अतिरिक्त एक लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ, कुल प्रतिबद्धता 1.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।'

आंध्र और आरएमजेड में 10 अरब डॉलर की साझेदारी

आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को दावोस में आरएमजेड ग्रुप के साथ 10 अरब डॉलर की रणनीतिक निवेश साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर डिजिटल, मिश्रित उपयोग और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। प्रस्तावित साझेदारी के तहत आरएमजेड ग्रुप विशाखापत्तनम के कपुलुप्पाडा चरण-1 आईटी पार्क में एक वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) पार्क विकसित करने की योजना बना रहा है।

चीन के इस कमाल से हमारे विश्वविद्यालय कुछ सीखेंगे

यहां स्कैन करें

हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएमबीएस

अभी एक सप्ताह पहले वैश्विक स्तर पर ग्लोबल रैंकिंग में एक धमाका हुआ है। यह धमाका नीदरलैंड्स की लीडन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग ने किया है। लीडन रैंकिंग में शीर्षस्थ 10 विश्वविद्यालयों में चीन का जे-जियांग विश्वविद्यालय नंबर एक पर आ गया है और उसने हार्वर्ड को पहले से तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। बाकी सात स्थानों पर भी चीन के कुछ शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों का कब्जा हो गया है। आज से 25 वर्ष पूर्व, चीन के जे-जियांग यूनिवर्सिटी शीर्ष 25 में भी नहीं थी। पिछले 25 वर्षों में चीनी विश्वविद्यालयों ने जो कुछ कर दिखाया है, इससे आने वाले दशकों में उच्च शिक्षा में भारी उतार-चढ़ाव के संकेत मिलते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने शीर्ष विश्वविद्यालय कहां खड़े हैं?

चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता रातोंरात संभव नहीं हुई है। इसके पीछे उनकी सरकार द्वारा 40 वर्षों से शोध को दी गई प्राथमिकता है। चीन में ज्यादातर विश्वविद्यालय सरकार की वित्तीय मदद से चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शोध-कार्यों को निर्देशित किया जाता है। चीनी विश्वविद्यालयों ने वैश्विक पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर प्रकाशन किए हैं। अंग्रेजी में उच्च गुणवत्ता वाले शोध-पत्रों का वैश्विक स्तर पर अधिक उल्लेख हुआ। चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता का राज राष्ट्रीय प्राथमिकता से जुड़ा शोध-कार्य है, जैसे सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में लक्षित अनुसंधान। इसके लिए चीन ने विदेश में शोधरत अपने नागरिकों को वापस बुलाया और वैश्विक प्रतिभाओं की भर्ती की गई। चीन का रिसर्च इकोसिस्टम और पैमाना भारत की तुलना में बहुत विशाल व मजबूत है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं- बड़े विश्वविद्यालय, बड़े शोध समूह, साझा प्रयोगशालाएं और टीम-आधारित शोध संस्कृति। ये विश्वविद्यालय शोध और विकास में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर कड़ी नजर बनाए रखते हैं और उद्योगों से मिलकर योजनाओं को अंजाम देते हैं।

चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता रातोंरात संभव नहीं हुई है। इसके पीछे उसकी सरकार द्वारा 40 वर्षों से शोध को दी गई प्राथमिकता है।

क्या चीन की सफलता से भारत कुछ सीख सकता है? इसके लिए हमें शोध को उच्च शिक्षा का केंद्र-बिंदु बनाना होगा। हमें अनुसंधान में निवेश और बढ़ाना होगा। भारत को विश्वस्तरीय रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। इसके लिए साझा प्रयोगशालाएं, शोध-परिसर और उत्कृष्टता केंद्र बनाने होंगे। ये सब काम सरकार अकेली नहीं कर पाएगी। निजी व अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा इसे मुमकिन करना होगा। शिक्षकों की वैश्विक स्तर पर भर्ती भी जरूरी है। प्रतिस्पर्द्धी वेतन, शोध में समर्थन, अकादमिक स्वायत्तता के क्षेत्रों में प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। हमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े शोध-कार्यों पर जोर देना होगा। पेटेंट, स्टार्ट-अप व सामाजिक प्रभाव पर और अधिक जोर देना होगा।

चीनी विश्वविद्यालयों की ग्लोबल रैंकिंग में सफलता से यह कतई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालयों में इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बजट 2025-26 में उच्च शिक्षा पर 50,067 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिसमें रिसर्च मद में आंशिक खर्च रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना पर भी 1,660 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय का प्रावधान रखा गया। इसी तरह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अंतर्गत अनुसंधान उत्कृष्टता और वैश्विक जुड़ाव को भारतीय उच्च शिक्षा के रूपांतरण का एक स्तंभ माना गया है। पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैकल्टी और विद्यार्थी का आदान-प्रदान और पीएचडी के संयुक्त निर्देशन पर जोर दिया गया है। वर्ष 2016 में शिक्षा मंत्रालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग शुरू की थी, जिससे पिछले एक दशक में शोध और विकास के क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक परिणाम आए हैं। इस रैंकिंग में शोध और विकास को 30 प्रतिशत वजन दिया जाता है। परंतु अभी यह स्वैच्छिक है, सिर्फ 40 प्रतिशत विश्वविद्यालय और 15 प्रतिशत कॉलेज ही इसमें भाग ले रहे हैं।

हालांकि, अनुसंधान पर अधिक कोष आवंटित किए जा रहे हैं, किन्तु वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शोध-आधारित रैंकिंग के लिए यह नाकाफी है। भारतीय विश्वविद्यालयों को ग्लोबल रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार से वित्तीय समर्थन की प्रबल जरूरत होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारत-यूएई औचक वार्ता का मतलब

यहां स्कैन करें

कंवल सिब्बल | पूर्व विदेश सचिव

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत आना अप्रत्याशित था। उनका यह दौरा भले ही दो घंटे का था, लेकिन इसका असर गहरा पड़ेगा।

सोमवार की देर शाम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत आना अप्रत्याशित था। भले ही, यह उनकी अब तक की पांचवीं यात्रा थी और बतौर राष्ट्रपति तीसरी, लेकिन इस दौरे की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने महज एक दिन पहले साझा की। फिर, उनका पूरा दौरा बमुश्किल दो घंटे का था। वह तकरीबन सवा चार बजे पालम हवाई अड्डे पर उतरे और सवा छह बजे अपने देश के लिए रवाना हो गए।

बेहद संक्षिप्त होने के बावजूद इस यात्रा के दीर्घकालिक निहितार्थ हैं। पहला, इसकी पहल संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से की गई थी, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जल्द कुछ ठोस बातचीत करना चाहते थे। यह 'मसला' पश्चिम एशिया से जुड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अभी इस खित्ते में उथल-पुथल मची हुई है। करीब तीन हफ्ते पहले यमन में सऊदी अरब के सैनिकों ने मुकल्ला शहर पर बमबारी इसलिए की थी, क्योंकि वहां कथित तौर पर यूएई से अलगाववादी गुट के लिए हथियारों की खेप आई थी। बेशक, दोनों देशों में यह कोई नई अदावत नहीं है, पर तीन महीने पहले सऊदी अरब व पाकिस्तान में रक्षा समझौता हुआ है और इसमें तुर्किये को भी शामिल करने की योजना है। ऐसे में, माना यही जा रहा है कि यूएई भी हमारे साथ ऐसा ही कोई रक्षा संबंध चाहता है, ताकि भारत इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाए और शक्ति का संतुलन बन सके।

नई दिल्ली इससे गाफिल नहीं है, इसलिए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने तत्काल साफ कर दिया कि नाहयान की यात्रा का गलत अर्थ नहीं निकाला जाए। सऊदी अरब को लेकर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट है और भारत वहां के समीकरण में एक के खिलाफ दूसरे को समर्थन देने की नीति नहीं अपनाएगा। यह उचित बयान है। वहां के तनाव में किसी एक का पक्ष लेना कूटनीतिक तौर पर घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं।

तमाम गतिविधियां चलाने पर सहमति जताई है।

वास्तव में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात का बढ़ता संबंध दोनों देशों को ही नहीं, कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। यहां इस्लामी दुनिया की चर्चा लाजिमी है। गौरतलब है, दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में राष्ट्रपति नाहयान पाकिस्तान गए थे। उस यात्रा का मूल मकसद तो स्पष्ट नहीं हो सका था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से यह जरूर कहा गया कि 'आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया'। ऐसे में, यूएई राष्ट्रपति के भारत आने से पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा होगा सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के बाद इस्लामाबाद का 'महिमा-गान' अब बंद हो सकता है।

इससे कथित 'इस्लामिक नाटो' पर भी दबाव पड़ेगा बेशक, तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने स्पष्ट किया है कि सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते में उसे भी शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन उन्होंने अभी तक साफ नहीं किया है कि उनका देश इसमें शामिल हो रहा है? इसमें इसलिए भी शक अधिक है, क्योंकि सऊदी अरब और तुर्किये के रिश्ते तल्ख हैं। रियाद 'मुस्लिम ब्रदरहुड' के खिलाफ है, जबकि तुर्किये इसका समर्थन करता है। फिर ऑटोमन साम्राज्य की यादें भी दोनों के बीच कटुता बढ़ाती हैं। ऐसे में, 'इस्लामिक नाटो' कितना सफल हो सकेगा, यह अभी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता।

हां, 'फाइनेंशियल एक्शन टास्ट फोर्स' यानी एफएटीएफ को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि भारत-अमीरात के गहराते रिश्ते पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं, गले नहीं उतरता। अमेरिका व पाकिस्तान में निकटता बढ़ी है, दोनों ने अभी-अभी आतंकवाद रोधी-अभियान में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है। इस रिश्ते से ट्रंप परिवार के अपने हित भी जुड़े हैं। ऐसे में, वह शायद ही पाकिस्तान के खिलाफ जाना चाहेगा और तुर्किये का समर्थन इस्लामाबाद को हासिल ही है। लिहाजा, नाहयान की यात्रा से एफएटीएफ में पाकिस्तान की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़ेगा।

कुल मिलाकर, राष्ट्रपति नाहयान का दौरा भारत-अमीरात रिश्ते को लेकर सुखद तस्वीर बनाता है ऊर्जा, व्यापार, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे तमाम क्षेत्रों में दोनों एक-दूसरे का लाभ उठा सकते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सवाल जवाब

2026 का बजट बाजार के लिए बड़ी घटना नहीं

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय शेयर बाजारों ने साल की शुरुआत घबराहट भरे माहौल में की है। जियो ब्लैकरॉक एएमसी के मुख्य निवेश अधिकारी ऋषि कोहली ने नई दिल्ली में पुनीत वाधवा को दिए साक्षात्कार में बताया कि प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में कटौती के लिए सरकार को काफी ज्ञापन मिले हैं। यह ऐसा मसला है जिस पर बाजार बारीकी से नजर रख रहे हैं। मुख्य अंशः

क्या अगले तीन से छह महीनों में बाजारों के लिए निराशा का माहौल हो सकता है?

पिछले कुछ महीनों से मेरा विचार यह रहा है कि बाजारों में थोड़ी सकारात्मकता बनी रहेगी, हालांकि अस्थिरता भी रहेगी। मुख्य जोखिम काफी हद तक वैश्विक हैं, विशेष रूप से भू-राजनीतिक घटनाक्रम। तथापि इनमें से अधिकांश जोखिमों का अब तक काफी अनुमान लगाया जा चुका है। एक महत्वपूर्ण कारक घरेलू आय वृद्धि रही है, जो लगभग पांच लगातार तिमाहियों से निराशाजनक रही है यानी 2024 की अंतिम तिमाही से लेकर वित्त वर्ष 2026 की पिछली तिमाही तक। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिसंबर और मार्च की तिमाहियों में मामूली सुधार की उम्मीद थी। अगर आय में क्रमिक सुधार जारी रहता है तो बाजार सकारात्मक रफ्तार बनाए रखने में सक्षम होंगे। फिर भी जनवरी और फरवरी के दौरान अस्थिरता की उम्मीद थी। इस अवधि में एक स्पष्ट सीजनल रुझान देखने में आता है- जब बाजार साल के अंत तक तेजी से बढ़ते हैं तो जनवरी-फरवरी में अक्सर स्थिरता या मामूली गिरावट देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों में आई गिरावट इसी पैटर्न के अनुरूप है और आश्चर्यजनक नहीं है। कुल मिलाकर, मेरा नजरिया थोड़ा सकारात्मक बना हुआ है। मैं किसी बड़े सकारात्मक बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आय में मामूली सुधार जारी रहता है तो धीरे-धीरे भरोसा वापस आ जाएगा।

आपने पहले कहा था कि मिडकैप शेयरों में आय बहाली पर नजर रखनी चाहिए। क्या ऐसा दिख रहा है?

नतीजों का सीजन अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। मुनाफे के लिहाज से देखें तो स्मॉलकैप की तुलना में लार्जकैप और मिडकैप शेयर बेहतर दिख रहे हैं। स्मॉलकैप शेयरों के आय की संभावना अभी भी कम है। लार्जकैप और मिडकैप शेयरों के बीच अगुआई समय-समय पर बदलती रह सकती है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे अब भी उम्मीद है कि आय संभावना के लिहाज से लार्जकैप और मिडकैप शेयर स्मॉलकैप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

वित्त वर्ष 2027 के लिए आय वृद्धि को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं?

बाजार के स्तर पर हम वित्त वर्ष 2027 के लिए लगभग 12 फीसदी की आय वृद्धि की उम्मीद करते हैं। चूंकि बाजार व्यापक रूप से समय के साथ आय का अनुसरण करते हैं। इसलिए उनसे भी उतना ही प्रतिफल मिलना चाहिए।

एकीकरण का मौजूदा दौर कब तक चलने की उम्मीद है?

जनवरी से मध्य मार्च तक आमतौर पर एकीकरण का दौर होता है। अगर मार्च तिमाही के परिणाम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो इसका बाजार पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन मामूली रूप से सकारात्मक आंकड़े भी अगले एक से डेढ़ वर्ष तक अपेक्षाकृत अच्छे प्रदर्शन के लिए आधार तैयार करने के लिए पर्याप्त होंगे।

आगामी केंद्रीय बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं?

मेरी अपेक्षाएं काफी कम हैं। राजकोषीय और मौद्रिक गुंजाइश सीमित है। इस वर्ष राजकोषीय घाटा करीब 4.4 फीसदी और अगले वर्ष 4.2 फीसदी रहने की संभावना है, जिसमें आगे की राह के लिहाज से मामूली समायोजन होंगे। पूंजीगत व्यय में कोई भी मामूली वृद्धि सकारात्मक होगी। लेकिन सेंटिमेंट ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। सेंटिमेंट में सुधार ही अंततः कंपनियों के निरंतर पूंजीगत व्यय में बदलता है, जो अभी तक निरंतरता के बजाय छिटपुट रहा है। कराधान मामले में बड़े बदलावों की गुंजाइश सीमित है। एसटीटी को लेकर सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन किया जा चुका है और बाजार इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। लेकिन अगर एसटीटी पर कुछ नहीं भी होता है तो भी मुझे यह कोई बड़ा नकारात्मक पहलू नहीं लगता, क्योंकि उम्मीदें पहले से ही कम हैं। इसके अलावा, बाजार अपेक्षाकृत नरम स्थिति में बजट का सामना कर रहे हैं। जब बाजार अत्यधिक आशावाद के साथ बजट देखते हैं तो निराशा का जोखिम अधिक होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इसलिए तीव्र नकारात्मक प्रतिक्रिया की संभावना सीमित दिखती है। दिन के दौरान कुछ तात्कालिक उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन संरचनात्मक रूप से कुछ खास नहीं होगा। कुल मिलाकर, बजट का बाजारों पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

सोने और चांदी के ईटीएफ में भारी निवेश देखने को मिला है। क्या कर संबंधी किसी भी बदलाव से निवेशकों का मनोबल गिर सकता है?

सोने और चांदी के ईटीएफ पर पहले से ही अपेक्षाकृत कम कर लगता है। यही कारण है कि कई निवेशक एक साल पूरा होने से पहले बड़ा लाभ होने पर भी बाहर नहीं निकलना चाहते। व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए कमोडिटी बाजारों का विकास वास्तव में फायदे की बात है। भारत पारंपरिक रूप से इक्विटी और बॉन्ड बाजार रहा है, जिसमें सोने और चांदी के अलावा कमोडिटी की भागीदारी सीमित रही है। समय के साथ तांबे जैसी कमोडिटी के लिए हाजिर बाजार और ईटीएफ विकसित करना, मौजूदा सोने और चांदी के उत्पादों पर कर को और सख्त करने की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक साबित होगा।

औरत क्यों सबसे आसान निशाना

औरत की देह जंग का मैदान नहीं है। कहीं हालात कुछ बिगड़ते ही औरतों का निशाने पर आ जाना वास्तव में कापुरुषों का युद्धघोष है। कहीं भी उपद्रव, हिंसा, युद्ध हो, सबसे पहले औरतों पर आफत टूटती है। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर की वह सामूहिक बलात्कार पीड़ित महिला बिना न्याय पाए दुनिया से चली गई। घर के बाहर ही नहीं, अंदर भी महिलाएं सबसे आसान निशाना बनती रही हैं। आखिर महिलाओं को कैसे-कब नसीब होगी वास्तविक समानता और सुरक्षा?

ईसा मसीह औरत नहीं थे
वरना मासिक धर्म
ग्यारह बरस की उमर से
उनको टिठकाये ही रहता
देवालय के बाहर।
बेथलाम और यरूशलम के बीच के
कठिन सफर में उनके
हो जाते कई तो बलात्कार
और उनके दुधमुंहे बच्चे
चालीस दिन और चालीस रातें
जब काटते सड़क पर -
भूख से बिलबिलाकर मरते एक-एक कर
ईसा को फुर्सत नहीं मिलती
सूली पर चढ़ जाने की भी।
मरने की फुर्सत भी कहां मिली सीता को
लव-कुश के लक्ष्य - भेद तक ?

हां ईसा मसीह औरत नहीं थे, पर ईसा मसीह की देह की तरह औरत की देह भी हर युद्ध, हर जातीय संघर्ष के दौरान प्रतिपक्षी द्वारा नृशंस कीलों से भेदकर चौराहे पर टांग दी जाती है कि सनद रहे। पर होता क्या है? कालांतर में यही देह शांति का पैगाम बनकर जनस्मृति में जीवित रहती है। स्त्री-आंदोलन की शुरुआत ही विश्वयुद्ध के तुरंत बाद नि:शस्त्रीकरण की गुहार से हुई और आज भी संघर्षग्रस्त-क्षेत्र (कॉन्फ्लिक्ट जोन) जिन शांति सेनानियों के समानांतर अभियानों से दीप्त हैं, फ्लोरेंस नाइटेंगेल की लालटेन की तरह, उनमें ज्यादातर स्त्रियां ही हैं।

अनामिका, कवयित्री

हर युग में कोमल स्त्री-देह पर युद्ध का इतिहास लिखा गया, जैसे छेनी से भेदकर पत्थर पर कोई भयावह पैगाम लिखा जाता है। यह प्रक्रिया वर्र कायरता की इन्तहा है। एथनिक क्लींजिंग, आरोपित संतान द्वारा अपनी तादाद बढ़ाकर प्रतिपक्षी को मजा चखाने की आदिम युक्ति भी।

मैतेई-कुकी समुदाय के आपसी संघर्ष में जो कुकी महिला गैंग रेप के बाद के यातनापूर्ण तीन वर्ष अस्पताल में बिताकर अंततः गुजर ही गई, उसके अपराधियों पर अब तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से उसके पिता बिना कारण बताए म्युनिसिपल्टी की नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए! यह उदाहरण लाखों ऐसे उदाहरणों में एक है, जहां पुरुष-समाज का पौरुष चूल्हे-भाड़ में गया हुआ जान पड़ता है! सबसे बड़ा कापुरुष तो वह है, जो बच्चियों की देह पर प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, पर धिक्कार के काबिल हैं वे सत्ताएं भी, चाहे वह पुरुष-सत्ता हो या राज्य-सत्ता, मजमा लगाकर जो टुकुर-टुकुर बस तमाशा देखती हैं। ऐसे कापुरुषों को तत्काल सजा दिलवाने की कोई पहल नहीं करतीं, सिर्फ इसलिए कि ये कापुरुष राजनीतिक रूप से दबंग हैं- किसी के बेटे, किसी के दामाद, किसी के भाई, किसी के भतीजे, किसी के चुनावी गुर्गे।

दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह तथ्य है कि जो सारे संसार पर नियंत्रण चाहता है, वह स्वयं अपनी दानवी वृत्तियों पर नियंत्रण न रख पाए और अपनी इंद्रियों को किसी राजनीतिक रूप से दबंग समूह का पालतू श्वान बनाकर गलियों में घूमे : जिस पर हुलका दिया, उसी पर झपट गए और पुरुषों से निबटा न गया, तो प्रतिपक्षी के स्त्री-बच्चों पर पशु-बल आजमा लिया। इस तरह पशु-बल वही आजमाता है, जिसका आत्मबल बिल्कुल छीज गया हो, धुंधला पड़ गया हो, जिसकी आत्मा का प्रकाश, और जो पुरुष कहलाने योग्य ही नहीं। पुरुष वह है, जिसके सद्गुण स्त्री में सम्मान का भाव जगाएं। जिसे पशु-बल दिखाकर जबर्दस्ती करनी पड़े, वह भी कोई पुरुष हुआ?

6000
से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को अकेले इस्लामिक स्टेट जैसे बर्बर आतंकी संगठन ने पिछले दस वर्षों में गुलाम बनाकर बाजार में बेचा है या शोषित किया है।

3600
से अधिक यौन हिंसा के मामले दुनिया के संघर्षरत क्षेत्रों में दर्ज किए गए, साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इनमें से 95 प्रतिशत मामलों में महिलाएं और लड़कियां शोषित रहीं।

महिलाओं के साथ अपराध

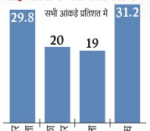

मणिपुर में बीस साल पहले

जनजातीय समाजों में महिलाओं पर मुसीबतें सबसे पहले टूटती हैं। मिसाल के लिए, सामूहिक बलात्कार की एक घटना 16 जनवरी, 2006 को हुई थी। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के परबंग और लुंगथुलियन में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। कथित तौर पर यूएनएलएफ (मणिपुर का एक उग्रवादी समूह) के सदस्यों द्वारा 21 आदिवासी महिलाओं का बलात्कार किया गया था। परबंग पुलिस थाना ने इस घटना के संबंध में 25 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं। आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए मणिपुर सरकार द्वारा 21 मार्च, 2006 को राजखोवा जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग के समक्ष 24 वर्षीय एक गृहिणी सहित लगभग 16 महिलाओं ने अपना पक्ष रखा। आयोग ने 30 मई, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, वह सामने नहीं आई।

मणिपुर में आज का हाल

मणिपुर में नाराजगी है। मई 2023 में मैतेई-कुकी जातीय संघर्ष के शुरुआती दिनों में अपहरण व सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई एक कुकी-जो पीड़िता का 10 जनवरी, 2026 को गुवाहाटी में इलाज के दौरान निधन हो गया। तीन साल पहले आरक्षण विवाद के चलते जातीय हिंसा भड़की थी। पीड़िता ने न्याय के लिए संघर्ष किया, लेकिन तन-मन का इलाज कराती जिंदगी से हार गई। उसकी मृत्यु ने मणिपुर में आक्रोश को फिर भड़का दिया है। कुकी-जो समाज नाराज है, तो फिर हिंसा की आशंका उत्पन्न हो गई है। ध्यान रहे, 18 वर्षीय महिला का 15 मई, 2023 को इम्फाल से एटीएम से पैसे निकालते समय अपहरण किया गया था। अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसे मैतेई महिलाओं के एक सतर्कता समूह, मीरा पैबी के सदस्यों ने ही बर्बर पुरुषों के हवाले किया था।

कृपया, अपने गिरेबां में झांकें भारतीय पुरुष

जो पुरुष अपने घर में महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनसे घर से बाहर किसी उम्मीद रखी जाए? मणिपुर की ही अगर बात करें, तो इस राज्य में महिलाएं घर के बाहर ही नहीं, अंदर भी बहुत शोषित हैं।

आक्रामक पति वाले पांच राज्य
- कर्नाटक
- बिहार
- मणिपुर
- तेलंगाना
- तमिलनाडु

कम आक्रामक पति वाले राज्य
- गोवा
- हिमाचल
- नगालैंड
- मिजोरम
- जम्मू-कश्मीर

50 हजार के करीब औरतें आजाद भारत में उग्रवादी के दौरान शोषित (अनुमानित)

90 हजार के करीब महिलाओं का देश के बंटवारे के समय यौन शोषण हुआ था।

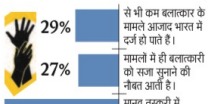

आज यह अत्यंत आवश्यक है कि दुनिया का हर शिक्षण संस्थान, मीडिया का हर प्रकाशन, हर किताब, हर सीरियल, हर फिल्म किसी-न-किसी ढंग से यह बात लोक के अवचेतन में उतारे कि औरतों की इज्जत तिनके की टोप नहीं है, जो किसी जहरीली आंधी में उड़ जाए। किसी जानवर के बीमार स्राव से या किसी दूसरी जबर्दस्ती से औरत की इज्जत नहीं जाती, उसकी जाती है, जो यह जबर्दस्तियां करता है। वह पुरुष की श्रेणी से गिरकर पागल भेड़िए की श्रेणी में आ जाता है। मां-बहन की गालियां औरतों का पर्दा नहीं खोलतीं, गालियां बकने वाले की अपनी परवरिश का भांडा जरूर फोड़ती हैं।

जबर्दस्ती के हादसे औरतों की जान भले ले लें, वे उनका मनोबल नहीं तोड़ सकते, जो अपनी इज्जत किसी की मुंह, किसी की पूंछ से बंधा हुआ नहीं देखतीं। यह ठीक है कि दुनिया के सारे अपराधों की आधारभूमि (प्राइम साइट) वही स्त्री-देह बना दी गई है, जिससे आप पैदा हुए हैं, पर स्त्रियां आदर्शों का परचम फहराने से बाज नहीं आतीं। स्त्री-आंदोलन दुनिया में इकलौता है, जिसने एक बूंद खून बहाए बिना हजार तरह के मनोवैज्ञानिक युद्ध जीते हैं - सिर्फ घर में नहीं, दुनिया के हर मोर्चे पर।

पश्चिम में नैन्सी शोदरी आदि मनोभाषिक विशेषज्ञों ने बलात्कारी पुरुषों के अंतःकरण का विश्लेषण करते हुए यह बताया है कि उनका मन स्त्री देह को शिकार की तरह देखता है, तो एक विशेष ईर्ष्या के तहत, जो लड़कों के मन में लड़कियों के लिए तब से होती है, जब पितृसत्ता उन्हें मां की गोद से जबर्दस्ती खींचकर अलग करती है। फ्रायड जिसे मिरर स्टेज कहते हैं, यानी वह अवस्था जब लड़के स्वयं को मां से अलग पहचानना सीखते हैं। संयोग से भाषिक विकास का समय भी यही होता है। इस समय लड़के के अपनी सबसे प्यारी शय यानी मां से अलग होने का जो झटका लगता है, उससे उनकी भाषा खुरदुरी और व्यवहार आक्रामक हो जाता है। आगे की कमी पितृसत्ता अपने पुलिसिया प्रशिक्षण से पूरी करती है। लड़कियां आराम से मां के पास बनी रहती हैं। उनका चित्त भाषा और चरित्र - विकास के इस मोड़ पर झटके नहीं खाता, तो उनकी अभिव्यक्ति सहज और स्नेहिल बनी रहती है। लैंगिक रूप से बंटा हुआ समाज बाद में लड़का-लड़की के बीच सहज दोस्ती विकसित होने नहीं देता। वह उसके लिए आकर्षण-विकर्षण, दोनों का केंद्र बन जाती है। दूर से उसे देखता हुआ वह ऐसा महसूस करता है, जैसे घात में बैठा भेड़िया भेड़ को देखकर महसूस करता होगा।

इस घातक स्थिति से बचने का एक उपाय यह है कि लड़कों को मां के संरक्षण में पाला जाए, अच्छे साहित्य, संस्कार और सिनेमा से पोषित किया जाए, ताकि स्त्रियां उनके लिए हव्वा न रहें, सहज दोस्त हो जाएं। इसे कहते हैं सेंसिटाइजेशन। जिन लड़कों का हृदय-संवाद मां-बहन व किताबों से बना रहता है, उनकी कोमल भावनाएं भी बची रहती हैं। किसी सियासी पार्टी के हुलकाने से वे श्वान या भेड़िया-वृत्ति से चालित नहीं होते हैं। उन्हें जल्द ही यह बात समझ में आ जाती है कि किसी तरह की जबर्दस्ती स्वाभिमान-सम्मत नहीं है। काम-क्रोध-लोभ का अतिरेक उन्हें कापुरुष तो बना सकता है, काम्य पुरुष हरगिज नहीं। इस तरह यह उनके पुरुषार्थ को ही भयावह चुनौती है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

पांच उपाय

महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत

ऋतु सारस्वत, समाजशास्त्री

वर्ष 2024 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कॉनफ्लिक्ट-रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस भी बताती है कि हमारी दुनिया में हिंसक संघर्षों और सामाजिक अशांति के दौरान महिलाएं सबसे पहले निशाना बनती हैं। आर्थिक मंदी आए या कहीं उपद्रव हो, सबसे पहले औरतों को ही नुकसान उठाना पड़ता है, तो सुधार के लिए ये पांच कदम तो जरूर उठाने चाहिए।

1 ऐसी हिंसा को बहुत गंभीरता से लिया जाए

हिंसा या दंगों की स्थिति में सरकार केवल कानून ही लागू नहीं करती, उसकी भाषा भी महत्वपूर्ण होती है। इस तथ्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम मिशेल फुको के सत्ता-विमर्श सिद्धांत को देख सकते हैं। जहां हिंसा को असाधारण अपराध के बजाय सामाजिक परिस्थिति का परिणाम मानकर गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ऐसी हिंसा को प्रभुत्व का प्रदर्शन मान लिया जाता है। हमारा कानून इस हिंसा को स्पष्ट रूप से चिह्नित करे, अपराधियों को दंड मिले, तभी प्रभावी रोकथाम संभव है।

2 पुरुष सत्ता की बुराइयों को खत्म कीजिए

आर डब्ल्यू कॉनेल का हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी सिद्धांत गौरतलब है। कॉनेल कहते हैं कि हिंसा केवल व्यक्तिगत आक्रोश नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से स्वीकृत छद्म पुरुषत्व का प्रदर्शन होती है। प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य को स्वीकार करना होगा कि दंगों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आकस्मिक नहीं, सामाजिक रूप से निर्मित पुरुष सत्ता का परिणाम है। जब तक प्रशासन इस संस्कृतिक संरचना को पहचानकर उस पर लक्षित हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक सुरक्षा के उपाय सतही बने रहेंगे।

3 शासन और समाज के बीच संवाद बढ़े

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सत्ता, नियंत्रण और सामाजिक संबंधों के असंतुलन के रूप में देखे जाने की जरूरत है। राजनीतिक विचारक हैना अरेंट अपने बायलेंस ऐंड पावर सिद्धांत में स्पष्ट करती हैं कि सत्ता और हिंसा एक ही प्रक्रिया के दो रूप नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों में अलग-अलग तरह से प्रकट होते हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जरूरी है कि शासन और समाज, दोनों स्तरों पर संवाद, विश्वास और न्याय की प्रक्रियाएं निरंतर सक्रिय रहें।

4 सामाजिक मर्यादाओं की चिंता कीजिए

जब समाज तीव्र सामूहिक भावनात्मक आक्रोश में प्रवेश करता है, तब व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत विवेक के बजाय सामूहिक चेतना द्वारा संचालित होने लगता है और इस तथ्य की पुष्टि समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम की कलेक्टिव एफरवेसेंस की अवधारणा करती है। आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ समाज के भीतर सामुदायिक हस्तक्षेप, संवाद और नैतिक संयम को सक्रिय रखा जाए। जब सामूहिक भावनाओं को समय रहते सामाजिक मर्यादाओं और संस्थागत संवाद के माध्यम से दिशा दी जाती है, तब हिंसा की प्रवृत्ति कमजोर पड़ने लगती है।

5 मौन टूटे, तो बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो

यदि ऐसी हिंसा को अस्पष्ट भाषा, चुप्पी या असहजता के कारण खुलकर संबोधित न किया जाए, तो मौन स्वयं हिंसा में सहायक बन जाता है। समाजशास्त्री बॉरेचू का विचार है कि यह मौन प्रतीकात्मक स्वीकृति का रूप ले लेता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यवस्था, समाज और मीडिया - तीनों स्तर पर पीड़िता-केंद्रित अभिव्यक्ति, भाषा की स्पष्टता और सार्वजनिक असंवेदनशीलता को चुनौती दी जाए। मौन टूटता है, तभी परिवर्तन होता है।